दैनिक

लद्दाख टुडे

वर्षः 01 अंकः 28 | लद्दाख, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्य 2 रुपए | RNI NO.: LAHIN/26/A7900

MALABAR
GOLD & DIAMONDS

संक्षिप्त...

ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने स्पष्ट किए अधिकार और पाबंदियां

नई दिल्ली। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने हाल ही में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों की कानूनी स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं।

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ओसीआई कार्ड धारक= भारतीय नागरिक नहीं हैं। यह कदम विदेशी भारतीय मूल के लोगों को मिलने वाले अधिकारों, छूटों और उन पर लागू होने वाले कानूनी प्रतिबंधों के बीच के भ्रम को दूर करने के लिए उठाया गया है।

ब्यूरो के अनुसार, ओसीआई कार्डधारकों को भारत यात्रा

■ शेष पेज 2...

दिल्ली पुलिस के 280 अफसरों को पीटाः स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से सीधा सवाल-जंतर-मंतर को किसने नोटिफाई किया?

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर–मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर डिनोटिफाई किए जाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की बातों को कांग्रेस ने भी जोर–शोर से उठाया है। लेकिन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दो टूक सवाल पूछ लिया है कि आखिर जंतर–मंतर को प्रदर्शन–स्थल के रूप में नोटिफाई किसने किया था?

बीजेपी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी अनबन जग–जाहिर है। अब ईरानी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने एक बार फिर से

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों को अनुचित भाषा का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी, अनुशासन और पेशेवर मर्यादा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कहा गया है।

सर्कुलर में बताया गया है कि जम्मू–कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के तहत, कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों, अधीनस्थों और आम जनता के साथ बातचीत करते समय विनम्रता, संयम और आपसी सम्मान बनाए रखें। प्रशासन ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपमानजनक, धमकी भरी या अनुचित भाषा का प्रयोग न करें। साथ ही, सभी प्रशासनिक सचिवों, संभागीय

■ शेष पेज 2...

----- जम्मू --------

अधिकतम – 42⁰C

न्यूनतम – 32⁰C

------ श्रीनगर ------

अधिकतम – 36⁰C

न्यूनतम – 24⁰C

एनएसजी स्थापना दिवसः आतंकवाद के खिलाफ तत्परता गर्व जगाती है

पीएम मोदी और नेताओं ने किया नमन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। वे साहस, सटीकता और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मिसाल हैं। आतंकवाद के खिलाफ

लोगों और देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एनएसजी की तत्परता नागरिकों के बीच गहरा विश्वास और गर्व की भावना जगाती है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि छैळ साहस, सटीकता और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के उनकी सतर्कता और हमारे लोगों तथा देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उनकी तत्परता, लोगों में गहरा विश्वास और गर्व की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ–साथ कई राजनीतिक नेताओं ने एनएसजी को उसके 42वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनएसजी कर्मियों को नमन करते हुए कहा कि इस बल का असाधारण साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व की बात है।

नबिन ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सभी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। एनएसजी का असाधारण साहस, पेशेवर रवैया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व की बात है। हम देश की सुरक्षा के प्रति एनएसजी कर्मियों की अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं और उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका वीरतापूर्ण जज्बा और समर्पण, राष्ट्र सेवा की सर्वोच्च परंपराओं का प्रमाण है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि एनएसजी की अटूट तत्परता और कर्तव्य के प्रति समर्पण, सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाते हैं। प्रधान ने कहा कि

■ शेष पेज 2...

उम्मीद के अनुरूप नहीं: सीएम उमर ने महिला सहकर्मी के साथ आईएएस अधिकारी के दुर्व्यवहार का लिया संज्ञान

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू/श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) की एक महिला अधिकारी के साथ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी का कड़ा संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि वरिष्ठ नौकरशाह का आचरण प्रथम दृष्टया अपेक्षित मानकों के अनुरूप नही है।

एक्स (ट्विटर) पर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जेकेएएस अधिकारी को किसी तरह की बदले की कार्रवाई का सामना न करना पड़े। आरोप है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने उन्हें नौकरी से निकालने की सिफारिश करने की धमकी दी थी।

अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑनलाइन मीटिंग का वीडियो देखा है। प्रथम दृष्टया, वरिष्ठ नौकरशाह का व्यवहार एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद एक कनिष्ठ जेकेएएस अधिकारी को दी गई धमकियां स्थिति को और भी खराब कर देती हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुख्य सचिव के सामने इस मुद्दे को बहुत सख्ती से उठाया है। दुर्भाग्य से, केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में आईएएस अधिकारियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार (लोक भवन) के पास होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने मुख्य

■ शेष पेज 2...

जूनियर के प्रति आईएएस अधिकारी की भाषा में शालीनता की कमी थी

उन्हें जम्मू–कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए: फारूक अब्दुल्ला

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को आईएएस अधिकारी कुमार

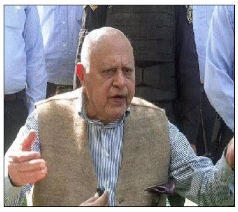

राजीव रंजन को जम्मू–कश्मीर से बाहर निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने एक महिला नौकरशाह के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके व्यवहार में शालीनता की कमी थी। तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनके कार्यकाल में, जब जम्मू–कश्मीर एक राज्य था, ऐसी कोई घटना हुई होती, तो वे उस अधिकारी को वापस उसी विमान में बिठाकर रवाना कर देते। अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह पूरी तरह गलत है; उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि उनमें उस शालीनता और आचरण की कमी है, जो एक अधिकारी में होनी चाहिए। अधिकारियों का यह

■ शेष पेज 2...

ईसीआई ने 17 राज्यों में शुरू किया एसएसआर, दलों को मिलेगी वोटर लिस्ट की आसान पीडीएफ

नइ दिल्ली। अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच, चुनाव आयोग ने दो ऐसे मुद्दों पर अपना रुख बदल लिया है, जिन पर लंबे समय से विपक्ष के साथ उसका टकराव चल रहा था। पिछले 24 घंटों में, दबाव का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने 17

■ शेष पेज 2...

देश में अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस, बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश

राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक

लद्दाख टूडे संवाददाता

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस समेत कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। नेहा बोरा के हालिया कमेंट को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता ने कहा कि ये लोग प्रेस कॉफ्रेंस में खुलकर कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने बांग्लादेश से प्रेरणा ली है। दूसरा ये डंके की चोट पर सरकार को गिराने की बात

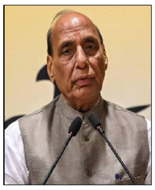

करते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से युवाओं को भड़का रहे ये स्पष्ट करता है कि इनका एकमात्र एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए है, वो सारे घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण के विचारों में लगाने की बजाय राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने के साधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र अराजकता फैलाना, संवैधानिक संस्थाओं की साख पर चोट करने या भारत की विकास यात्रा में बाधा डालने का लाइसेंस नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की कल की टिप्पणी भी मैं समझता हूं कि इसी ओर एक संकेत है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का सम्मान करना भी आवश्यक है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर व्यवधान की

■ शेष पेज 2...

असीम मुनीर भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं

सुशांत सरीन के बयानों के मुरीद हुए जम्मू–कश्मीर के पूर्व डीजीपी

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य रणनीतिक सलाहकार सुशांत सरीन के बयानों के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए उनके बयानों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सुशांत सरीन दो बयान मुझे बहुत पसंद आए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने ही लोगों को मारकर भारत के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब लोग श्पाकिस्तान जिंदाबादश नहीं कहते, बल्कि श्पाकिस्तान से जिंदा भागश कहते हैं।

दरअसल, सुशांत सरीन एक निजी चौनल के इंटरव्यू में

पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे कभी यह ठीक से समझ नहीं आया कि पाकिस्तान के शून्य शासक असीम मुनीर को भारतीय पसंद क्यों नहीं करते। वह ईश्वर का भेजा हुआ एक वरदान हैं। मेरा मतलब है, अगर वे अपने ही देश का कबाड़ा कर रहे हैं और आपस में फूट डाल रहे हैं, तो यह भारत के लिए अच्छा कैसे नहीं हो सकता? माओ के शब्दों में कहें तो, श्ओक (पाकिस्तान) में बहुत भारी उथल–पुथल है, स्थिति बहुत बेहतरीन है।

सुशांत सरीन ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपने घरेलू संकटों को संभालने में संघर्ष कर रहा है, भले ही उसका

■ शेष पेज 2...

पंजाब में ड्रग्स का कारोबार फल–फूल रहा है, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में हुई दो घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगेगी–पहली घटना दिरबा की है, जहां दबाव में आकर एक पिता ने जहर खा लिया; और दूसरी घटना मानसा की है, जहां नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में, शाह ने कहा कि पंजाब आज ड्रग्स, गैंगस्टरिज़्म और संगठित अपराध के बढ़ते खतरों से जूझ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा कि आखिर

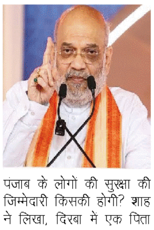

पंजाब के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? शाह ने लिखा, दिरबा में एक पिता का दबाव में आकर जहर खा लेना, और मानसा में नशा विरोधी आवाज़ उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या – इन घटनाओं ने पंजाब की कानून–व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शाह ने बताया कि झोटा के पिता ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उनके विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इन दोनों घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा। नशा विरोधी कार्यकर्ता

■ शेष पेज 2...

डॉ. जितेंद्र ने पंजाब भाजपा कार्यकारिणी बैठक में मुख्य भाषण दिया, विकसित पंजाब का किया आह्वान

संगरूर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित पंजाब के बिना श्विकसित भारतश का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के विजन में पंजाब का विकास एक अहम हिस्सा होना चाहिए।

संगरूर में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पूरी तरह शामिल होने के लिए पंजाब को एक डबल इंजन सरकार की जरूरत है। उन्होंने

विकास–केंद्रित शासन, जवाबदेही और नशीले पदार्थों की समस्या, भ्रष्टाचार तथा राज्य के सामने मौजूद अन्य चुनौतियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में हुई यह बैठक, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का हिस्सा थी। इसमें सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया। बैठक में पंजाब भाजपा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, सह–प्रभारी वरिंदर सचदेवा और डॉ. अल्का गुर्जर, तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ सहित कई अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे।

बैठक में पंजाब की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक

■ शेष पेज 2...

जेएंडके सरकार ने एक महिला जेकेएएस अधिकारी के साथ आईएएस अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार की जांच के दिए आदेश

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू/श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को

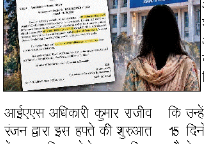

आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में एक महिला जेकेएएस अधिकारी के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार की विस्तृत जांच के आदेश दिए है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि 2004 बैच की आईएएस अधिकारी और आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त– सचिव मनदीप कौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि उन्हें यह आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार, जीएडी

■ शेष पेज 2...

एक महिला जेकेएएस अधिकारी के साथ आईएएस अधिकारी का अपमानजनक बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जा सकताः महबूबा

श्रीनगर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि एक महिलाजेकेएएस अधिकारी के साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन का अजीब और अपमानजनक बर्ताव बर्दाश्त

नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाएं।

श्रम और रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव, रंजन उस समय विवादों में आ गए, जब आरोप लगा कि उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान, गांदरबल की सहायक निदेशक (रोजगार) बीनीश वानी के साथ बातचीत में अभद्र भाषा

■ शेष पेज 2...

मुख्य सचिव डुलू ने जम्मू और श्रीनगर के लिए बहु–आयामी ट्रैफिक प्रबंधन योजना की समीक्षा की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुलू ने आज ट्रैफिक प्रबंधन पर बनी बहु–विषयक समिति (एमडीसी) की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एक व्यापक कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य जम्मू और श्रीनगर शहरों में ट्रैफिक जाम को कम करना, शहरी आवागमन को बेहतर बनाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है।

बैठक में सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

इसके साथ ही, ट्रैफिक नियमन, पार्किंग प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, सड़क बुनियादी ढांचे, कानून लागू करने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता से जुड़े विभिन्न अंतर–विभागीय कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया गया।

समन्वित और परिणाम–उन्मुख प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने संबंधित नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे दोनों शहरों में विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक साइनेज (संकेतकों) की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच के लिए नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने संबंधित

■ शेष पेज 2...

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

ओसीआई कार्डधारक भारतीय...

और निवास के लिए कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उन्हें भारत आने–जाने के लिए आजीवन मल्टी–परपज वीजा मिलता है और देश में रहने के दौरान फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा, घरेलू हवाई यात्रा के किराए और राष्ट्रीय उद्यानों, संग्रहालयों व ऐतिहासिक स्मारकों में प्रवेश शुल्क के मामले में ओसीआई कार्डधारकों से भारतीय नागरिकों के समान ही शुल्क लिया जाता है।

ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्डधारकों भारत में अचल संपत्ति (जैसे घर या जमीन) खरीदने या बेचने की अनुमति है, लेकिन वे कृषि भूमि, फार्महाउस और बागान वाली संपत्तियां नहीं खरीद सकते। इन विशेषाधिकारों के बावजूद, ओसीआई कार्डधारक भारतीय चुनावों में वोट नहीं डाल सकते और न ही संसद, राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्य बन सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यह भी कहा कि वे कुछ खास संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकते, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस के 280...

कांग्रेस नेतृत्व को अपने उसी अंदाज में घेरना शुरू कर दिया है। अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने जंतर–मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डिनोटिफाई किए जाने के दिल्ली पुलिस के फैसले का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें आईना भी दिखा दिया है।

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को जंतर–मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों समेत कई पुलिस अफसरों के साथ प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई कथित मारपीट की निंदा करने की चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बर्बरता के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जब उनसे पूछा गया कि जंतर–मंतर तो परंपरागत प्रदर्शन स्थल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उसे किसने नोटिफाई किया था?

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आरोप लगाया कि 280 पुलिस अफसरों के साथ प्रदर्शनकारियों ने ज्यादती की, लेकिन राहुल गांधी की जुबान नहीं खुली। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्होंने ऐसा नहीं करने की एक भी अपील क्यों नहीं की?

बता दें कि जब 14 अक्टूबर को जंतर–मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर शपथ पत्र में किए गए वादे का उल्लंघन करने के आरोप में सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली की एक अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा तो राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, जंतर–मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेंगे।

तथ्यों की पड़ताल करें तो पहले राजधानी में इस तरह के विरोध–प्रदर्शन इंडिया गेट के पास बोट क्लब पर होते थे। लेकिन, 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के व्यापक प्रदर्शन के दौरान बोट क्लब की सूरत और सेहत बिगड़ गई। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद पैदा हुए माहौल में 1993 में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस प्रदर्शन–स्थल को औपचारिक रूप से जंतर–मंतर पर शिफ्ट कर दिया और तब से लेकर वहीं पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसे अब डिनोटिफाई करके तीन अलग वेन्यू पर शिफ्ट किया गया है।

जम्मू–कश्मीर सरकार ने...

आयुक्तों और विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आचरण संबंधी इन दिशानिर्देशों का हर स्तर पर सख्ती से पालन किया जाए।

उम्मीद के अनुरूप नहीं:...

सचिव को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि जेकेएएस अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर जम्मू–कश्मीर एक पूर्ण राज्य होता, तो जिस आईएएस अधिकारी को युवा जेकेएएस अधिकारी के साथ बदसलूकी करते देखा गया है, उसे उसके आचरण की जांच पूरी होने तक सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से संबद्ध कर दिया जाता। अब्दुल्ला ने कहा, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि आईएएस अधिकारियों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी एक सही उदाहरण पेश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दुर्व्यवहार और धमकियों जैसी घटनाओं को दबाया न जाए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर श्मिशन युवाश की समीक्षा बैठक के दौरान रंजन और सहायक निदेशक बीनीश वानी के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया। इस बहस में श्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनश (एनआरआरएलएम) की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही थी। जेकेएएस समुदाय ने वानी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और सार्वजनिक अपमान की निंदा की है और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जूनियर के प्रति आईएएस...

कर्तव्य है कि वे लोगों की बात सुनें, जो केवल अपनी समस्याएं उनके सामने रखना चाहते हैं।

अब्दुल्ला ने आगे कहा, लेकिन उसके बाद चिल्लाना और श्बाहर निकलो, बाहर निकलोश कहना–यह पूरी तरह गलत है। उन्हें जम्मू–कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए। वे ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन्हें यहां होना चाहिए। अगर वे यहां अधिकारी बने रहते हैं, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई अधिकारी हो या मंत्री, वे लोगों की सेवा करने के लिए ही होते हैं।

अब्दुल्ला ने कहा, वे यहां लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हैं, न कि उनका अपमान करने या उन्हें अपशब्द कहने के लिए। उनका आचरण पूरी तरह अनुचित था। आज सोशल मीडिया पर उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख और शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सभी सिविल सेवकों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है; उन्हें (अन्य अधिकारियों को) उन्हें फटकार लगानी चाहिए। उनका व्यवहार एक आईएएस अधिकारी के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि श्अगर जम्मू–कश्मीर एक राज्य होता, तो इस आईएएस अधिकारी को उनके आचरण की जांच पूरी होने तक सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से संबद्ध कर दिया जाताश, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा कि वे तो उस अधिकारी को बाहर ही निकाल देते। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में, जब जम्मू–कश्मीर एक राज्य था, ऐसी घटना का होना तो ष्सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होतीं। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। उसे सिर्फ पद से हटाया ही नहीं जाता, बल्कि बाहर निकाल दिया जाता। अगर मैं उस समय (सत्ता में) होता, तो वह दो मिनट से ज़्यादा इस पद पर नहीं रह पाता। मैं उसे वापस उसी विमान में बिठाकर रवाना कर देता, वरिष्ठ अब्दुल्ला ने कहा।

ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, गुरुवार को मिशन युवा की समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन और जेकेएएस (जेकेएएस) अधिकारी बीनीश वानी के बीच तीखी बहस होती दिखी।

ईसीआई ने 17 राज्यों...

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) की घोषणा की है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की ऐसी पीडीएफ कॉपी देने का वादा किया है जिसे आसानी से पढ़ा जा सके–जो कि उसके अपने ही पुराने रुख से एक बड़ा बदलाव है।

हाल के वर्षों में विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को बार–बार उठाया है। दूसरे ऐलान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब खुद चुनाव आयोग ने निजता (प्राइवेसी) से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची जारी करने का विरोध किया था। यह समय काफी अहम है। कॉकरोच जनता पार्टीश और विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। आरोप है कि मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में गड़बड़ियां की गई हैं। पूरे देश में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया के चलते 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, जिससे भारी अफरा–तफरी मच गई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर के कारण, चुनाव आयोग ने विशेष एसएसआर प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके जरिए नए पात्र मतदाताओं (जिनमें 18 वर्ष के होने वाले लोग भी शामिल हैं) का पंजीकरण किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जेन जेड मतदाता 2024–25 की एसएसआर प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण नहीं करा सके, जिससे काफी नाराजगी पैदा हुई।

एसआईआर एक अधिक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ देने पड़ते हैं या पिछली मतदाता सूचियों से मिलान (मैपिंग) करना पड़ता है। एसएसआर मतदाता सूचियों को अपडेट करने और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की एक नियमित, वार्षिक प्रक्रिया है। इसलिए, मतदाताओं को खुद को पिछली विस्तृत पुनरीक्षण प्रक्रिया से मैप करने की ज़रूरत नहीं होती।

देश में अराजकता...

राजनीति करने के बजाय जनमत का सम्मान करते हुए अपनी राजनीतिक भूमिका पर आत्ममंथन करना चाहिए। यह मेरी राहुल गांधी को सलाह है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्गज बीजेपी नेता ने कहा कि देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की तर्ज पर शासन बदलना चाहते हैं और एक प्रेस वार्ता में खुलकर कहते हैं कि उसने शासन बदलने की प्रेरणा बांग्लादेश से ली है। तो दूसरा डंके की चोट पर सरकार गिराने की बात करता है। राजनाथ बोले– इससे यह साफ होता है कि इनका इकलौता एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करना और देश में आग लगाना है। शासन बदलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि उनकी लड़ाई चुनाव सुधार, ‶प्, ज्ञानेश कुमार, देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने की उनकी साजिश है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, कई काले अध्याय आपको मिलेंगे। चुनाव आयोग और इस देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को किस प्रकार अपनी कठपुतली बनाकर रखा था, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1993 में कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग में अचानक बदलाव कर दिया। रातों–रात चुनाव आयोग में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए।

एनएसजी स्थापना दिवस:...

एनएसजी स्थापना दिवस पर, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बहादुर जवानों को उनके साहस, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों का सामना करने में दिखाए गए असाधारण पेशेवर कौशल के लिए सम्मानित करता है। उनकी अटूट तत्परता और कर्तव्य के प्रति समर्पण, सेवा की सर्वोच्च परंपराओं का प्रतीक हैं। जम्मू–कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि असाधारण चुनौतियों का सामना करने और देश की रक्षा करने के लिए एनएसजी बल की तत्परता, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनके सर्वोच्च संकल्प को दर्शाती है। नबी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस पर, मैं हमारे बहादुर एनएसजी जवानों को उनके अनुकरणीय साहस, अटूट समर्पण और पेशेवर कौशल के उच्चतम मानकों के लिए सलाम करता हूँ। असाधारण चुनौतियों का सामना करने और देश की रक्षा करने के लिए उनकी तत्परता, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनके सर्वोच्च संकल्प को दर्शाती है। हम उनके बलिदानों और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करते हैं और भारत को सुरक्षित रखने में उनके अमूल्य योगदान के लिए इन साहसी योद्धाओं को नमन करते हैं।

असीम मुनीर भारत...

सैन्य नेतृत्व मध्य पूर्व में एक बड़ी भूमिका की तलाश में हो। सरीन ने यह समझाते हुए कि वे क्यों मानते हैं कि मुनीर के कदम अंततः भारत के पक्ष में काम कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि असीम मुनीर ने पाकिस्तान के भीतर इतनी आग और चिंगारियां भड़का दी हैं। इससे बेहतर की मैं कामना भी नहीं कर सकता था। यह तर्क तीन परस्पर जुड़े संकटों पर टिका है, घरेलू राजनीति पर सेना का बढ़ता नियंत्रण, आतंकवाद का निरंतर बने रहना, और सऊदी अरब की दखलअंदाजी।

सुशांत सरीन का कहना है कि मुनीर की नीतियां पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को और बढ़ा रही हैं, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जाहिर तौर पर उन्हें पसंद नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है कि भारतीयों को उन्हें पसंद करना चाहिए, क्योंकि वह उस देश को बर्बाद कर रहे हैं।

एक कमजोर और अस्थिर पड़ोसी देश सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। लेकिन सरीन का तर्क यह है कि मुनीर के फैसले पाकिस्तान के अपने ही हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं – चाहे वह देश के भीतर की स्थिरता हो या क्षेत्रीय कूटनीति। क्या आसिम मुनीर अपनी सत्ता मजबूत कर रहे हैं, या पाकिस्तान को और गहरे संकट में धकेल रहे हैं?

मुख्य सचिव डुलू...

सभागीय आयुक्तों से कहा कि वे प्रगति पर कड़ी नजर रखें और कमियों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने ट्रैफिक विभाग से कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ई–डीएआर) पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करें, ताकि दुर्घटना–संभावित स्थानों और विशेष समय पर होने वाले ट्रैफिक जोखिमों की पहचान की जा सके। उन्होंने जोर दिया कि ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती उन चिह्नित श्हॉटस्पॉटश और श्ब्लैकस्पॉटश (दुर्घटना संभावित क्षेत्रों) के अनुसार होनी चाहिए, ताकि नियमों का पालन बेहतर ढंग से हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सके।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा, ताकि पूरे जम्मू–कश्मीर में चलने वाले भारी यात्री वाहनों (विशेषकर स्कूल बसों) का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया जा सके। पार्किंग प्रबंधन के संबंध में, उन्होंने आम जनता की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर अतिरिक्त ऑन–स्ट्रीट पार्किंग स्थल तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अनियंत्रित पार्किंग से होने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के शहरी केंद्रों में अतिरिक्त पार्किंग स्थल बनाकर पार्किंग नीति को सख्ती से लागू किया जाए।

इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कामकाज पर ध्यान देते हुए, मुख्य सचिव ने इस प्रणाली को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में श्फेशियल रिकग्निशन सिस्टमश (एफआरएस) को शामिल किया जाए, ताकि नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके और यात्रियों तथा वाहन चालकों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पीएम–राहत योजना को लागू करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जम्मू–कश्मीर में सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्रों पर समय पर इलाज मिलने से वंचित न रहना पड़े।

बैठक में वेंडिंग ज़ोन, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईआरएडी), ई–कोर्ट, ट्रैफिक और परिवहन विभागों द्वारा लागू किए गए प्रवर्तन उपायों, और सड़क चौड़ीकरण तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े उन कार्यों की भी समीक्षा की गई, जो ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं या प्रस्तावित हैं।

जेएंडके सरकार ने एक...

के अतिरिक्त सचिव अमित वर्मानी को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) नियुक्त किया गया है।

श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव रंजन तब विवादों में आ गए, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक के दौरान, श्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनश की भूमिका को लेकर गांदरबल की सहायक निदेशक (रोजगार) बीनिश वानी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दोनों अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसकी जम्मू–कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) बिरादरी ने कड़ी निंदा की है।

एक महिला जेकेएएस...

का इस्तेमाल किया। यह बैठक 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनश की भूमिका को लेकर थी।

महबूबा ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, इस तरह का अजीब और अपमानजनक बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को तुरंत भारत सरकार के सामने यह मामला उठाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, जिस पर पहले से ही अवैध बंदूक लाइसेंस जारी करने के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर रंजन और वानी के बीच तीखी बहस के वीडियो सामने आए, जिसके बाद गुरुवार को जम्मू–कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के अधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की।

डॉ. जितेंद्र ने पंजाब...

स्थिति, किसानों की चिंताएं, नशीले पदार्थों का सेवन, सरकारी कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता, कानून–व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक नेतृत्व पर बात करते हुए, डॉ. सिंह ने इसे भारत की राजनीतिक और शासन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उसके बाद केंद्र सरकार में उनके नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि एक स्थिर नेतृत्व ने भारत की वैश्विक छवि, राष्ट्रीय आत्मविश्वास और विकास प्राथमिकताओं को बदलने में बड़ा योगदान दिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्य के विकास की संभावनाओं के लिए बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास, कृषि क्षेत्र को समर्थन और स्वास्थ्य सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए 43,527 करोड़ रुपये और रेलवे में 34,488 करोड़ रुपये के निवेश का जिक्र किया, साथ ही रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की बात भी कही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, उन्होंने बताया कि पंजाब के लगभग 11 लाख किसान इसके लाभार्थी हैं और इस योजना के अंतर्गत 6,552 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने एम्स बठिंडा, मोहाली में टाटा मेमोरियल सेंटर की कैंसर सुविधा और राज्य में 565 जन औषधि केंद्रों का भी जिक्र किया, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा सस्ती दवाओं के महत्व पर जोर दिया।

मंत्री ने सिंचाई और बिजली उत्पादन के संदर्भ में शाहपुर कंडी परियोजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कृषि उत्पादकता और क्षेत्रीय विकास में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर, लंगर की वस्तुओं पर जीएसटी छूट, और सिख इतिहास व विरासत को संजोने वाली पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इन कदमों को पंजाब की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पंजाब की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, भरोसेमंद सिंचाई व्यवस्था, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसर बहुत जरूरी हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब के विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी शासन और जवाबदेही का होना आवश्यक है। उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य की आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इन मुद्दों पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है।

पंजाब में ड्रग्स...

झोटा की मंगलवार को मानसा के एक व्यस्त बाज़ार में एक मेडिकल स्टोर मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्टोर मालिक अश्वनी कुमार ने झोटा पर तब गोली चलाई, जब झोटा उससे एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने के बारे में सवाल कर रहा था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

शाह ने जिस पहली घटना का जिक्र किया, वह 7 सितंबर को संगरूर के दिरबा में गुलज़ार सिंह की आत्महत्या से जुड़ी है। गुलज़ार के परिवार का आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से अपने इलाके में ड्रग्स की सप्लाई के बारे में सवाल पूछने पर, गुलज़ार को परेशान किया गया और जातिसूचक टिप्पणियां की गईं, जिसके चलते उसने जहर खा लिया।

बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों ने पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे को जोर–शोर से उठाया है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने एक्स पोस्ट में शाह ने कहा, पंजाब में ड्रग्स का कारोबार फल–फूल रहा है, संगठित अपराध का खतरा बढ़ रहा है, और जो लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मान को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि पंजाब की जनता प्रचार नहीं, बल्कि नतीजे चाहती है।

"भगवंत मान जी, पंजाब के लोग वादे नहीं, जवाब चाहते हैं; वे घोषणाएं नहीं, नतीजे चाहते हैं। उन्हें ड्रग नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहिए, और अपराधियों को मिल रहे किसी भी राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच चाहिए।"

गृह मंत्री ने कहा, "आज मैं पंजाब की जनता के सामने अपना यह संकल्प दोहराता हूं कि जब पंजाब में हमारी सरकार आएगी, तो हम एक नशा–मुक्त, गैंगस्टर–मुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट हैरू ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम, और कानून का ऐसा शासन हो जिससे कोई भी नागरिक डर के साये में जीने को मजबूर न हो।"

HELP LINE

IMPORTANT CONTACT NUMBERS – UT LADAKH

POLICE DEPARTMENT (SPs)

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	EMAIL
1	SP Leh	Shree Raam R (IPS)	8899222100	01982-244031	ssp-leh1@police.ladakh.gov.in
2	SP Nubra	Sh. Stanzin Losal (JKPS)	9419037139 8825045363	–	spnubra@gmail.com (Temporary)
3	SP Changthang	Sh. Syed Zaheer Abass (JKPS)	9797995888	7006368375	sp-changthang@police.ladakh.gov.in
4	SP Sham	Sh. Aijaz Malik (JKPS)	9419923000	6006424325	sp-sham@police.ladakh.gov.in
5	SP Kargil	Sh. Niten Yadav (IPS)	9999339994	01985-232645/232704	sspkargil@police.ladakh.gov.in Fax No. 232645
6	SP Drass	Sh. Istiqaq A. Kacho (JKPS)	8492097235	–	sp-drass@police.ladakh.gov.in
7	SP Zanskar	Sh. Rigzen Sangdup	9419287779 6006164711	–	sp-zanskar@police.ladakh.gov.in

DEPUTY COMMISSIONERS

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	PA TO DC / EMAIL
1	DC Leh	Sh. Romil Singh Donk (IAS)	7982319218	01982-252685	Stanzin – 8494072166
2	DC Kargil	Sh. Rakesh Kumar (IAS)	8604286353	01985-232216	Skarma Gurmat – 9622254259
3	DC Changthang	Sh. Nitish Rajora (IAS)	7053991969	(Temporary)	PA to DC – Kunzes Dolma 6005297553
4	DC Nubra	Sh. Mukul Beniwal (IAS)	8800308665	01982-252049	–
5	DC Zanskar	Sh. Omkar Rajendra Gundage (IAS)	8668894331	–	dc-zanskar@ladakh.gov.in
6	DC Sham	Smt. Kunzes Angmo	9419179108	–	–
7	DC Drass	Sh. Imteeaz Kacho (JKAS)	–	–	–

These numbers are for public assistance and urgent communication only.

FOR ANY EMERGENCY, DIAL 112

Created by Universal Document Converter

हियरिंग हेल्प और डब्ल्यूएसए ने जम्मू में नए बेस्टसाउंड सेंटर 3.0 के साथ हियरिंग केयर तक पहुंच बढ़ाई

डब्ल्यूएस आडियोलाजी और सूर्योदय फाउंडेशन ने जम्मू के 75 गरीब लोगों को 150 हियरिंग एड्स दान करके किया लान्च

जम्मू। हियरिंग हेल्प प्राइवेट लिमिटेड ने हियरिंग केयर में ग्लोबल लीडर, डब्ल्यूएस आडियोलाजी के साथ मिलकर जम्मू में आफिशियली अपना नया बेस्टसाउंड सेंटर 3.0 खोला है, जिससे पूरे भारत में इसकी पहुंच और मजबूत हुई है। यह सेंटर डब्ल्यूएसए के बेस्टसाउंड कान्सेप्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाता है, जो हियरिंग केयर के लिए कंज्यूमर–फर्स्ट अप्रोच लाता है, जो क्लिनिकल से हटकर पर्सनल की ओर जाता है।

ओपनिंग के मौके पर डब्ल्यूएसए ने सूर्योदय फाउंडेशन के साथ मिलकर जम्मू के 75 गरीब लोगों को 150 हियरिंग एड्स दान किए, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए हियरिंग केयर को और आसान बनाने का उनका साझा कमिटमेंट और मजबूत हुआ। 17–ए/डी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के पास, गांधी नगर, जम्मू–में मौजूद, बीएससी 3.0 बेस्टसाउंड सेंटर कॉन्सेप्ट पर बना है, जिसे क्लिनिकल एक्सपर्टाइज़ और मॉडर्न हेल्थकेयर से लोगों को मिलने वाले अनुभव के बीच के अंतर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बड़े पैमाने पर ग्लोबल टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के ज़रिए बेहतर बनाए गए, जम्मू में इस कॉन्सेप्ट का लॉन्च, इस साल की शुरुआत में बैंगलोर में बेस्टसाउंड सेंटर के सफल लॉन्च के बाद, उत्तरी भारत में उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को लाने के डब्ल्यूएसए के कमिटमेंट को दिखाता है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, भारत में लगभग 63 मिलियन लोग सुनने में गंभीर कमी के साथ जीते हैं। दुनिया भर में, 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग कुछ हद तक सुनने में कमी के साथ जीते हैं, जिनमें से 430 मिलियन को सुनने में बहुत ज़्यादा कमी है, यह संख्या 2050 तक बढ़कर 700 मिलियन होने का अनुमान है। चुनौती के पैमाने के बावजूद, देखभाल तक पहुँच सीमित है। स्टिग्मा, कम जानकारी, कीमत, और यह सोच कि हियरिंग एड्स आखिरी उपाय है, जैसे फैक्टर्स लोगों को मदद लेने से रोकते हैं। बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर, स्पेशलिस्ट हियरिंग केयर तक पहुंचना और भी मुश्किल है।

डब्ल्यूएसए इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, अविनाश पवार ने कहा, "हियरिंग केयर तक पहुंच इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि आप कहां रहते हैं या आप कितना खर्च कर सकते हैं।" बीएससी 3.0 के साथ, जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब उसी स्टैंडर्ड की केयर, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस मिलता है जो हम दुनिया भर में देते हैं। आखिरकार, यह लोगों को उनके परिवारों, उनके काम और उनके समुदायों से फिर से जुड़ने में मदद करने के बारे में है।"

सेंटर में डायग्नोस्टिक्स, काउंसलिंग, प्रोडक्ट ट्रायल्स और आफ्टरकेयर के लिए डेडिकेटेड ज़ोन के साथ एक ओपन, इंटरैक्टिव लेआउट है। विज़िटर्स क्लिनिकल अपॉइंटमेंट की फॉर्मैलिटी से मुक्त सेटिंग में अपनी गति से हियरिंग सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेट–ऑफ–द–आर्ट हियरिंग इवैल्यूएशन इक्विपमेंट, डिजिटल हियरिंग एड फिटिंग सूट्स, और इमर्सिव साउंड ज़ोन से इक्विप्ड, यह सेंटर लोगों को रियल–लाइफ लिसनिंग एनवायरनमेंट में हियरिंग सॉल्यूशन एक्सपीरियंस करने में इनेबल करता है। इस पूरे प्रोसेस में, ट्रेंड हियरिंग केयर प्रोफेशनल हर कस्टमर को शुरुआती असेसमेंट और डिवाइस चुनने से लेकर लगातार देखभाल और सपोर्ट तक गाइड करते हैं।

हियरिंग हेल्प प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जॉन ज़रगर ने कहा, हमें डब्ल्यूएसए के साथ मिलकर जम्मू में बेस्टसाउंड सेंटर लाने की खुशी है। 2019 से, हमने देखा है कि जम्मू और कश्मीर में कई लोग एडवांस्ड हियरिंग केयर के लिए बड़े शहरों में जाते हैं या इसके बिना ही रह जाते हैं। यह कोलेबोरेशन हमें वर्ल्ड–क्लास ऑडियोलॉजिकल एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल जानकारी देता है, और साथ मिलकर हमने एक ऐसा सेंटर बनाया है जिसके बारे में हमें विश्वास है कि यह सुनने के बारे में हमारी कम्युनिटी की सोच को बदल देगा। हमने जो बनाया है, उस पर हमें गर्व है, और हम इन दरवाज़ों के ज़रिए अपनी कम्युनिटी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।"

डब्ल्यूएसए के साथ पार्टनरशिप में, सूर्योदय फ़ाउंडेशन, जो 2016 में बना एक चैरिटेबल नॉन–प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है, ने जम्मू और आस–पास के इलाकों के 75 ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की पहचान की, जिन्हें सुनने में दिक्कत है लेकिन वे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। ट्रेंड हियरिंग केयर प्रोफ़ेशनल्स ने हर जोड़ी हियरिंग एड्स को जाँचा और लगाया। कुल मिलाकर डब्ल्यूएसए ने 150 हियरिंग एड्स डोनेट किए और डब्ल्यूएसए इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अविनाश पवार ने खुद दिए।

कई लाभार्थियों के लिए, लंबे समय से केवल खर्च ही सुनने की देखभाल तक पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा रहा है। अगर समय रहते इलाज न किया जाए, तो सुनने की क्षमता कम होने से व्यक्ति धीरे–धीरे समाज से कट सकता है। इससे घर पर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, काम और आजीविका पर असर पड़ता है, और सामाजिक जीवन में शामिल होने का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। बीएससी 3.0 के सहयोग से, देखभाल केवल हियरिंग एड लगाने तक ही सीमित नही रहेगी। हर लाभार्थी को लगातार फॉलो–अप सपोर्ट मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हियरिंग एड लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से काम करते रहें।

पवार ने आगे कहा, सुनने की देखभाल उन सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, न कि सिर्फ उन लोगों तक जो किसी सेंटर में जाकर इसका खर्च उठा सकते हैं। हियरिंग हेल्प और सूर्योदय फाउंडेशन के साथ मिलकर, हमने जम्मू में अपना मिशन शुरू किया है। इसके ज़रिए हम 75 लोगों को उनके परिवारों, साथियों और समुदायों से फिर से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। बीएससी 3.0 जैसे सेंटर का असली मकसद यही है।

जॉन ज़रगर ने कहा, जम्मू में हम रोज़ाना अपने समुदाय की सेवा करते है और आज हम जिन लोगों से मिले, यह सेंटर असल में उन्हीं के लिए बनाया गया है। हमारी टीम हर लाभार्थी को लगातार फॉलो–अप केयर देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, हम पूरे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में हियरिंग अवेयरनेस ड्राइव और स्क्रीनिंग कैंप के ज़रिए अपने प्रयासों का विस्तार कर रहे है।

सांसद गुलाम अली खटाना ने कुपवाड़ा में लगाया जनता दरबार, जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश

कुपवाड़ा। राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने शुक्रवार को कुपवाड़ा के टाउन हॉल में जनता दरबार आयोजित कर जिले में विकास कार्यों की प्रगति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों की समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सांसद ने विभिन्न विभागों के कामकाज की क्षेत्रवार समीक्षा की। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और प्रतिनिधियों ने बिजली, पेयजल, सड़क संपर्क, परिवहन, राशन वितरण, दूरसंचार, वन संबंधी मामलों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं।

खटाना ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे करने चाहिए, ताकि लोगों की वास्तविक समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

सांसद ने जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए और विकास कार्यों को पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, कुपवाड़ा को जनता दरबार में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर दो सप्ताह के भीतर समेकित रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जनता दरबार के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सांसद और प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। इस पहल को जिले में जवाबदेह प्रशासन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया।

बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए: बद्रीनाथ शर्मा

मंडलायुक्त डा. विकास कुंडल को सौंपा ज्ञापन, फसलों और पशुधन के नुकसान का व्यापक सर्वेक्षण कराने की मांग

जम्मू। अपनी पार्टी किसान विंग के अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्मा ने हाल ही में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि, अचानक आई बाढ़ और आकाशीय बिजली से किसानों तथा पशुपालकों को हुए नुकसान का व्यापक आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने अपनी पार्टी एससी सेल के अध्यक्ष बोधराज के साथ जम्मू के मंडलायुक्त डा. विकास कुंडल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में शर्मा ने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों की खड़ी फसलों, बागवानी उत्पादों, सब्जियों, पौधशालाओं और कृषि ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कई पशुपालकों को भी अपने पशुओं के घायल होने या मरने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभागों की संयुक्त टीमें गठित कर समयबद्ध सर्वेक्षण कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन जम्मू–कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि

उपकरणों पर अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं तथा कई बार कर्ज भी लेते है। फसलों को नुकसान पहुंचने से उनकी आय प्रभावित होती है और परिवारों के सामने कर्ज चुकाने तथा घरेलू खर्च पूरे करने की चुनौती खड़ी हो जाती है। बद्रीनाथ शर्मा ने छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने, प्रभावित परिवारों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने तथा पशुओं के नुकसान पर भी उचित सहायता देने की मांग की। उन्होंने घायल पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सुविधा, चारे की व्यवस्था और क्षतिग्रस्त पशुशालाओं की मरम्मत हेतु सहायता देने पर जोर दिया। उन्होंने सिंचाई नहरों, ग्रामीण सड़कों और कृषि ढांचे की मरम्मत, फसल बीमा दावों के शीघ्र निपटारे तथा जरूरतमंद किसानों के कृषि ऋणों के पुनर्गठन पर विचार करने की भी अपील की। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोहन कुंडल, जनक राज, रमन शर्मा, तीर्थ सिंह, तीर्थ कुमार और महेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

गांव बडैयाल ब्राह्मण देरिया में वार्षिक दंगल का हुआ आयोजन

जम्मू के बीनिया पहलवान ने पहले मुकाबले पर किया कब्जा

आरएस पुरा। आरएस पुरा क्षेत्र के गांव बडैयाल ब्राह्मण देरिया में शुक्रवार को वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया इसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ अन्य राज्यों से आए हुए नामी एवं टिकट पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने–अपने जौहर दिखाएं। दंगल का पहला मुकाबला जम्मू के बीनिया पहलवान तथा पंजाब पठानकोट के जग्गा पहलवान के बीच हुआ जिसमें जम्मू के बीनिया पहलवान ने जीत हासिल कर बडैयाल ब्राह्मण देरिया का वार्षिक दंगल अपने नाम कर लिया। इसके अलावा दूसरे मुकाबले में आरएस पुरा के काका पहलवान तथा अक्षय पहलवान के बीच हुआ जो बराबरी पर रहा। इसके अलावा दंगल में दो दर्जन से ज्यादा मुकाबला देखने में मिले जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ पंजाब, हरियाणा से आए हुए नामी एवं दिग्गज पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर

दिखाएं। इस मौके पर विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिन्होंने इस दंगल की शुरुआत करवाई तथा विजेता एवं उपविजेता रहे पहलवानों को इनाम राशि एवं माली देकर सम्मानित किया। इसके अलावा पंचायत के पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा भाजपा नेता हरबंस चौधरी बिल्ला, दंगल कमेटी के सतपाल चौधरी, नन्नू चौधरी, अश्वनी चौधरी सोहन लाल तथा दर्शन चौधरी सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक ने दंगल कमेटी के सदस्यों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस तरह के दंगल होते रहने चाहिए क्योंकि इस नौजवान पीढ़ी को नशा जैसी पूरी आदतों से दूर रहने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि दंगल कमेटी इसलिए भी प्रशंसा की पात्र है कि दंगल में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय पहलवानों को मौका दिया गया है। इस मौके पर दंगल कमेटी के हरबंस चौधरी बिल्ला ने बताया कि हर वर्ष छठे नवरात्रि पर गांव बडैयाल ब्राह्मण देरिया में विशाल दंगल का आयोजन करवाया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ अन्य प्रदेशों से भी आए हुए नामी एवं दिग्गज पहलवान हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि गांव में दंगल का आयोजन पिछले लंबे समय से करवाया जा रहा है जिसका मकसद नौजवान पीढ़ी को नशा जैसी पूरी आदतों से दूर रखना है और अपने प्राचीन खेलों के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर दंगल कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी अपने–अपने विचार रखें।

KIND ATTENTION RAIL PASSENGERS!

IMPORTANT INFORMATION

RUN OF MORE FESTIVAL SPECIAL TRAINS - 2026

In order to clear extra rush of passengers during this Festival Season, Railways have decided to run the following additional Festival Special Trains as per details given below:-

04092/04091 Delhi Jn. - Howrah Jn. - Delhi Jn. Reserved Festival Special Express Train — 02 Trips

Train No. 04092 ARR.	Train No. 04092 DEP.	STATIONS	Train No. 04091 ARR.	Train No. 04091 DEP.
----	00:30	Delhi Jn.	15:50	----
08:40	----	Howrah Jn.	----	10:10

DAYS OF RUN: **04092** Ex. **Delhi Jn.** on 17.10.2026 and **04091** Ex. **Howrah Jn.** on 18.10.2026.
STOPPAGES: Tundla Jn., Govindpuri, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugraha Narayan Road, Guraru, Gaya Jn., Koderma, Hazaribagh Road, NSC Bose J Gomo, Dhanbad Jn., Asansol, Durgapur & Barddhaman Stations.
ACCOMMODATION: AC 2 Tier & AC 3 Tier.

04404/04403 Shakur Basti - Patna Jn. - Shakur Basti Unreserved Festival Special Express Train — 16 Trips

Train No. 04404 ARR.	Train No. 04404 DEP.	STATIONS	Train No. 04403 ARR.	Train No. 04403 DEP.
----	15:15	Shakur Basti	15:00	----
14:30	----	Patna Jn.	----	15:40

DAYS OF RUN: **04404** Ex. **Shakur Basti** on 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 & 14.11.2026 and **04403** Ex. **Patna Jn.** on 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 & 15.11.2026.
STOPPAGES: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh, Tundla, Govindpuri, Subedarganj, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara & Danapur Stations.
ACCOMMODATION: Sleeper & General.

04410/04409 Shakur Basti - Jhanjharpur Jn. - Shakur Basti Unreserved Festival Special Express Train — 16 Trips

Train No. 04410 ARR.	Train No. 04410 DEP.	STATIONS	Train No. 04409 ARR.	Train No. 04409 DEP.
----	13:00	Shakur Basti	01:40	----
16:00	----	Jhanjharpur Jn.	----	18:15

DAYS OF RUN: **04410** Ex. **Shakur Basti** on 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 & 14.11.2026 and **04409** Ex. **Jhanjharpur Jn.** on 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 & 15.11.2026.
STOPPAGES: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Jn., Kanpur Central, Unnao Jn., Aishbagh, Gonda Jn., Gorakhpur Jn., Kaptanganj Jn., Bagaha, Narkatiaganj Jn., Sikta, Raxaul Jn., Ghorasahan, Bairagnia, Sitamarhi, Janakpur Road, Kamtaul, Shisho Halt. & Sakri Jn. Stations.
ACCOMMODATION: Sleeper & General.

09617/09618 Udaipur City- Delhi Sarai Rohilla - Udaipur City Festival Special Express Train (Weeky) — 12 Trips

Train No. 09617 ARR.	Train No. 09617 DEP.	STATIONS	Train No. 09618 ARR.	Train No. 09618 DEP.
----	21:15	Udaipur City	04:00	----
11:15	----	Delhi Sarai Rohilla	----	13:45

DAYS OF RUN: **09617** Ex. **Udaipur City** on every Wednesday from 21.10.2026 to 25.11.2026 and **09618** Ex. **Delhi Sarai Rohilla** on every Thursday from 22.10.2026 to 26.11.2026.
STOPPAGES: Mavli Jn., Chanderia, Bhilwara, Bijainagar, Ajmer Jn., Kishangarh, Phulera, Ringas Jn., Nim Ka Thana, Narnaul, Ateli, Rewari Jn., Gurgaon & Delhi Cantt Stations.
ACCOMMODATION: AC 2 Tier, AC 3 Tier, AC 3 Tier Economy, Sleeper & General.

08407/08408 Khurda Road Jn. - Anand Vihar (T) - Khurda Road Jn. Festival Special Express Train — 02 Trips

Train No. 08407 ARR.	Train No. 08407 DEP.	STATIONS	Train No. 08408 ARR.	Train No. 08408 DEP.
----	12:15	Khurda Road Jn.	10:45	----
22:30	----	Anand Vihar (T)	----	00:30

DAYS OF RUN: **08407** Ex. **Khurda Raod Jn.** on 17.10.2026 and **08408** Ex. **Anand Vihar (T)** on 19.10.2026.
STOPPAGES: Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur K Road, Bhadrakh, Balasore, Hijli, Midnapore, Bishnupur, Bankura, Adra, NSC Bose J Gomo, Koderma, Gaya Jn., Dehri On Sone, Sasaram, Bhabua Road, Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn., Subedarganj, Govindpuri, Tundla Jn. & Ghaziabad Stations.
ACCOMMODATION: AC 2 Tier, AC 3 Tier, Sleeper & General.

04070/04069 New Delhi – Howrah Jn. – New Delhi Reserved Festival Special Superfast Express Train — 02 Trips

Train No. 04070 ARR.	Train No. 04070 DEP.	STATIONS	Train No. 04069 ARR.	Train No. 04069 DEP.
----	08:20	New Delhi	18:45	----
10:50	----	Howrah Jn.	----	15:00

DAYS OF RUN: **04070** Ex. **New Delhi** on 17.10.2026 and **04069** Ex. **Howrah Jn.** on 18.10.2026.
STOPPAGES: Aligarh Jn., Kanpur Central, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara, Patna Jn., Bakhtiyarpur Jn., Kiul Jn., Jhajha, Jasidih Jn., Madhupur Jn., Chittaranjan, Asansol Jn., Durgapur, Bardhaman & Bandel Stations.
ACCOMMODATION: AC 2 Tier & AC 3 Tier.

04085/04086 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra - New Delhi Reserved Festival Special Express Train — 02 Trips

Train No. 04085 ARR.	Train No. 04085 DEP.	STATIONS	Train No. 04086 ARR.	Train No. 04086 DEP.
----	14:00	New Delhi	23:30	----
03:00	----	Shri Mata Vaishno Devi Katra	----	10:00

DAYS OF RUN: **04085** Ex. **New Delhi** on 17.10.2026 and **04086** Ex. **Shri Mata Vaishno Devi Katra** on 18.10.2026.
STOPPAGES: Sonipat, Panipat Jn., Kurukshetra Jn., Ambala Cantt, Dhandari Kalan, Jalandhar Cantt, Pathankot Cantt, Martyr Captain Sunil Kr Choudhary Kathua, Jammu Tawi & Martyr Captain Tushar Mahajan Stations.
ACCOMMODATION: AC 2 Tier, AC 3 Tier, Sleeper & General.

For any kind of information, passengers are requested to contact RailMadad Helpline No. 139 or visit Indian Railways website https://enquiry.indianrail.gov.in or NTES App.

04485/04486 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra - New Delhi Reserved Festival Special Express Train — 04 Trips

Train No. 04485 ARR.	Train No. 04485 DEP.	STATIONS	Train No. 04486 ARR.	Train No. 04486 DEP.
----	14:15	New Delhi	23:30	----
03:00	----	Shri Mata Vaishno Devi Katra	----	10:00

DAYS OF RUN: **04485** Ex. **New Delhi** on 18.10.2026 & 20.10.2026 and **04486** Ex. **Shri Mata Vaishno Devi Katra** on 19.10.2026 & 21.10.2026.
STOPPAGES: Sonipat, Panipat Jn., Kurukshetra Jn., Ambala Cantt, Dhandari Kalan, Jalandhar Cantt, Pathankot Cantt, Martyr Captain Sunil Kr Choudhary Kathua, Jammu Tawi & Martyr Captain Tushar Mahajan Stations.
ACCOMMODATION: 1st AC, AC 2 Tier, AC 3 Tier, Sleeper & General.

04231/04232 Varanasi Jn. - Jammu Tawi - Varanasi Jn. Reserved Festival Special Express Train — 02 Trips

Train No. 04231 ARR.	Train No. 04231 DEP.	STATIONS	Train No. 04232 ARR.	Train No. 04232 DEP.
----	13:40	Varanasi Jn.	17:40	----
21:00	21:10	Lucknow	10:05	10:15
15:20	----	Jammu Tawi	----	17:00

DAYS OF RUN: **04231** Ex. **Varanasi Jn.** on 18.10.2026 and **04232** Ex. **Jammu Tawi** on 19.10.2026.
STOPPAGES: Jaunpur Jn., Ayodhya Dham Jn., Ayodhya Cantt, Lucknow, Shahjahanpur Jn., Bareilly, Moradabad, Saharanpur Jn., Ambala Cantt. Jn., Ludhiana Jn., Jalandhar Cantt. Jn. & Pathankot Cantt Stations.
ACCOMMODATION: AC 3 Tier, Sleeper & General.

04201/04202 Varanasi Jn. - Ayodhya Dham Jn. - Varanasi Jn. Unreserved MEMU Festival Special Train (Daily) — 88 Trips

Train No. 04201 ARR.	Train No. 04201 DEP.	STATIONS	Train No. 04202 ARR.	Train No. 04202 DEP.
----	16:20	Varanasi Jn.	04:00	----
21:40	----	Ayodhya Dham Jn.	----	22:20

DAYS OF RUN: **04201** Ex. **Varanasi Jn.** and **04202** Ex. **Ayodhya Dham Jn.** from 18.10.2026 to 30.11.2026 (Daily).
STOPPAGES: Shivpur, Birapatti, Babatpur, Pindra Road Halt, Khalispur, Trilochan Mahadeo, Jalalganj, Sarkoni, Zafarabad Jn., Jaunpur Jn., Mahgawan, Mihrawan, Manikala Halt, Khetasarai, Shahganj Jn., Bilwai, Tulsinagar, Malipur, Jafarganj, Akbarpur, Katahri, Goshainganj, Ulna Bhari, Bilhar Ghat & Darshannagar Stations.
ACCOMMODATION: General.

TEMPORARY EXTENSION OF TRAINS

14212 New Delhi - Agra Cantt. Intercity Express will be extended up to Gwalior Station w.e.f 05.11.2026 to 14.11.2026 & 14211 Agra Cantt. - New Delhi Intercity Express will originate from Gwalior Station w.e.f 06.11.2026 to 15.11.2026

Train No. 14212 ARR.	Train No. 14212 DEP.	STATIONS	Train No. 14211 ARR.	Train No. 14211 DEP.
----	17:40	New Delhi	10:00	----
		No Change		
22:05	22:20	Agra Cantt Jn.	05:40	05:45
23:18	23:20	Dhaulpur	04:35	04:37
00:10	00:12	Morena	03:28	03:30
01:40	----	Gwalior Jn.	----	02:40

64426 New Delhi - Ghaziabad EMU will be extended up to Aligarh Jn. & 64429 Ghaziabad - New Delhi EMU will originate from Aligarh Jn. w.e.f 05.11.2026 to 14.11.2026

Train No. 64426 ARR.	Train No. 64426 DEP.	STATIONS	Train No. 64429 ARR.	Train No. 64429 DEP.
----	09:55	New Delhi	17:20	----
		No Change		
10:45	10:55	Ghaziabad	16:10	16:30
11:20	11:21	Maripat	15:12	15:13
11:26	11:27	Dadri	15:01	15:02
11:31	11:32	Boraki Halt	14:55	14:56
11:37	11:38	Ajaibpur	14:50	14:51
11:45	11:46	Dankaur	14:42	14:43
11:53	11:54	Wair	14:34	14:35
11:59	12:00	Chola	14:28	14:29
12:04	12:05	Gangraul Halt	14:23	14:24
12:09	12:10	Sikandarpur	14:18	14:19
12:15	12:16	Khurja Jn	14:12	14:13
12:21	12:22	Kamalpur	14:05	14:06
12:26	12:27	Danwar	14:00	14:01
12:35	12:36	Somna	13:51	13:52
12:44	12:45	Kulwa	13:42	13:43
12:50	12:51	Mahrawal	13:36	13:37
13:00	-----	Aligarh Jn	-----	13:30

It is notified for the information of rail passengers that Northern Railway has decided to extend the periodicity of the run of following Festival Special Trains as per details given below:-

Train No. & Name	Date of Additional Trips	No. of Trips
04052 New Delhi - Howrah Jn. Festival Special	17.10.2026 & 21.10.2026	02
04051 Howrah Jn. - New Delhi Festival Special	17.10.2026, 19.10.2026 & 23.10.2026	03
04081 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra Festival Special	26.10.2026 to 06.11.2026	12
04082 Shri Mata Vaishno Devi Katra - New Delhi Festival Special	27.10.2026 to 07.11.2026	12

Rest other instructions will hold good.

RailMadad Helpline No. **139**

Visit RailMadad website:- www.railmadad.indianrailways.gov.in — Download RailMadad app.

Please join us on

NORTHERN RAILWAY
Your Convenience - Our Concern
Visit us at : www.nr.indianrailways.gov.in

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

बैरिकेड्स के पीछे

लोकतंत्र की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसकी संस्थाओं पर जनता का भरोसा हो, बल्कि तब होती है जब नागरिक उन पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में बदलाव को लेकर बढ़ता टकराव भारत के सामने ठीक ऐसी ही एक परीक्षा पेश करता है। युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान अब वोट देने के अधिकार, इकट्ठा होने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े एक बड़े संघर्ष में बदल गया है।

श्कॉकरोच जनता पार्टीश (सीजेपी) के नेताओं को बार–बार हिरासत में लेना, प्रदर्शनकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना और जंतर–मंतर को प्रदर्शन के लिए तय जगह के दर्जे से हटा देना, यह दिखाता है कि जन–विरोध को दबाने के लिए सरकार का रवैया और भी सख्त होता जा रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह कानून–व्यवस्था बनाए रखे, हिंसा रोके और प्रदर्शनों को नियंत्रित करे। लेकिन इन जिम्मेदारियों के नाम पर ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए जा सकते, जिनसे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना लगभग नाममकिन हो जाए। मेट्रो स्टेशनों को बंद करना, परिवहन व्यवस्था में रुकावट डालना और लोगों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना – इन प्रतिबंधों से जनता का गुस्सा और भड़क सकता है। जंतर–मंतर को प्रदर्शन के लिए तय जगहों की सूची से हटाना चिंताजनक हैय याद रहे कि पिछली सरकारों ने श्बोट क्लबश और श्इंडिया गेट लॉनश को प्रदर्शन के लिए बहुत करीब मानकर, जंतर–मंतर को ही प्रदर्शन की जगह के तौर पर चुना था।

एक लोकतांत्रिक सरकार को उचित नियमों के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें ऐसी अनुमतियों पर निर्भर कर देना चाहिए जो असल में नागरिकों के अधिकारों को ही खत्म कर दें। अगर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचना ही मुश्किल हो या वहां की व्यवस्थाएं लोगों को शामिल होने से हतोत्साहित करें, तो दूसरी जगहों का विकल्प होने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार का मतलब सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि आप वहीं और तभी बोल सकते हैं, जब प्रशासन को यह सुविधाजनक लगे। हालांकि, मतदाता सूची से जुड़े इस विवाद को बिना सोचे–समझे किसी एक पक्ष के दावों को मान लेने के बजाय, बहुत ध्यान से जांचने की जरूरत है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव का मकसद अयोग्य नामों को हटाना है। वहीं, विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में असली मतदाताओं के नाम भी कट सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। चूंकि बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, इसलिए पारदर्शी तरीके से इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। साथ ही, अगर पक्षपातपूर्ण हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं, तो उन्हें सबूतों के जरिए साबित भी किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी का इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला, विवाद को सुलझाने का एक संस्थागत रास्ता खोलता है। न्यायिक जांच से यह पता चल सकता है कि क्या यह प्रक्रिया कानून के अनुसार है और क्या इसमें नागरिकों के वोट देने के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा की गई है। लेकिन कानूनी लड़ाई, प्रशासनिक पारदर्शिता की जगह नहीं ले सकती – खासकर तब, जब चुनाव पूरी तरह से लाखों लोगों के सही डेटा पर निर्भर हों। अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक अपना वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। ब्श्रच की निरंतरता ने युवाओं के लामबंद होने को दबाने के राजनीतिक नतीजों को भी उजागर कर दिया है। बेरोजगारी, परीक्षाओं में अनियमितताओं और न्यायपालिका की एक विवादास्पद टिप्पणी से उपजे गुस्से ने इसे एक ऐसा आधार दिया है, जो पारंपरिक राजनीतिक निष्ठाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका प्रभाव अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह विरोध–प्रदर्शन को ठोस और साक्ष्यों पर आधारित मांगों में बदल पाता है।

इस बीच, विपक्षी दलों को यह दिखाना होगा कि चुनावी निष्पक्षता को लेकर उनकी चिंता, सत्ताधारी दल के साथ उनकी तात्कालिक प्रतिस्पर्धा से कहीं बढ़कर है। भारत की संस्थाओं को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जबरन खामोशी का मतलब लोगों का भरोसा बहाल होना है। चुनाव आयोग को अपनी समीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता साबित करनी चाहिए, सरकार को शांतिपूर्ण असहमति की रक्षा करनी चाहिए, और अदालतों को समय रहते मामलों की जांच–परख करनी चाहिए। लोकतांत्रिक सत्ता की असली पहचान यह नहीं है कि वह विरोध–प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा दे, बल्कि यह है कि वहां इकट्ठा हुए नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए वह कितनी तत्पर है।

पंजाब में नशे का तांडव: वर्दी बनी त्रासदी

ललित गर्ग

पंजाब की धरती कभी शौर्य, पराक्रम, मेहनत, उद्यमशीलता और जीवटता के लिए जानी जाती थी। इसी मिट्टी के नौजवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और खेतों में पसीना बहाकर देश का अन्न भंडार भरा। लेकिन आज उसी पंजाब की पहचान नशे के बढ़ते कारोबार, युवाओं की बर्बादी और ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव से जुड़ती जा रही है। यह केवल एक राज्य की सामाजिक त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन–व्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति की गंभीर परीक्षा है। जिस पंजाब के युवाओं के हाथों में कभी तलवार, हल और तिरंगा शोभा देते थे, वहां आज नशे ने अनेक हाथों को बेबस और अनेक परिवारों को बदहवास कर दिया है। विडंबना देखिए कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों की है, यदि उन्हीं के घर से करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामद होने की खबर सामने आती है, तो यह व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने का मामला इसी सड़ांध की ओर संकेत करता है। यह घटना महज एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसमें अपराध रोकने के लिए नियुक्त व्यक्ति ही कथित तौर पर अपराध के संदेह के घेरे में आ जाए। यह तो वही स्थिति हुई कि 'बाड़ ही खेत को खाने लगे', तो फसल की रखवाली कौन करेगा? जिस पुलिस के कंधों पर नशा तस्करों को पकड़ने का दायित्व है, यदि उसी व्यवस्था के भीतर ऐसे तत्व पनपने लगें, तो आम नागरिक का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए।

पंजाब में नशे का कारोबार अब गलियों, गांवों और कस्बों

तक अपनी जड़ें फैला चुका है। कभी नशे की समस्या को सीमावर्ती क्षेत्रों या शहरी युवाओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज सिंथेटिक ड्रग्स सहित विभिन्न मादक पदार्थों की उपलब्धता ने संकट को और व्यापक बना दिया है। युवा पीढ़ी का एक हिस्सा नशे की गिरफ्त में आकर अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भविष्य गंवा रहा है। कहीं मां की गोद सूनी हो रही है, कहीं वृद्ध पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन रहा है और कहीं परिवार का कमाऊ सदस्य नशे की लत के कारण स्वयं अपने परिजनों पर बोझ बन रहा है। 'घर का चिराग ही घर में अंधेरा कर दे', इससे बड़ी विडंबना क्या होगी! नशे की लत केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक ताने–बाने को भीतर तक खोखला कर देती है। इस संकट की गंभीरता सरकारी आंकड़ों और पुलिस की कार्रवाइयों से भी समझी जा सकती है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार दस महीनों में पंजाब पुलिस ने 10,524 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 153 बड़े ऑपरेटर शामिल थे। इस दौरान 790 किलोग्राम हेरोइन, 860 किलोग्राम अफीम और अन्य मादक पदार्थों के साथ 13 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी जब्त की गई तथा नशे के कारोबार से जुड़ी 208 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ये आंकड़े कार्रवाई के पैमाने को अवश्य दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ आखिर राज्य में पहुंच कैसे रहे हैं? इतनी गिरफ्तारियों और जब्ती के बावजूद यदि नशे की उपलब्धता और लत पर निर्णायक अंकुश नहीं लग रहा, तो स्पष्ट है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों–ज्यों दवा की' जैसी स्थिति से बचने के लिए गिरफ्तारियों की संख्या से आगे बढ़कर नशे की आपूर्ति, वित्तीय नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की पड़ताल करनी होगी।

पाकिस्तान से लगी पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर लंबी सीमा इस चुनौती को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की आशंकाएं सीमा प्रबंधन को और जटिल बनाती हैं। वर्ष 2026 में अब तक पंजाब की सीमा से 183 ड्रोन जब्त किए जाने का उल्लेख इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। सीमा पार से संचालित तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करना आवश्यक है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बाहरी ताकतों पर डालकर राज्य के भीतर की कमजोरियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। यदि स्थानीय तस्कर, संगठित गिरोह और भ्रष्ट तंत्र मिलकर काम कर रहे हों, तो सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ–साथ भीतर भी कठोर कार्रवाई करनी होगी। 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने वाली जांच ही बता सकती है कि इस काले कारोबार में कौन मोहरा है, कौन खिलाड़ी और कौन पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने नशामुक्ति और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अनेक दावे किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे जमीन पर उतना परिवर्तन ला पाए हैं, जिसकी अपेक्षा पंजाब की जनता ने की थी? सत्ता में आने से पहले नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के वादे करना आसान है, लेकिन उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाना राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और निरंतर जवाबदेही मांगता है। यदि नशे की उपलब्धता बनी हुई है, युवा लगातार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और तस्करी के नेटवर्क बार–बार सक्रिय हो जाते हैं, तो सरकार की रणनीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। केवल छापेमारी, गिरफ्तारी और घोषणाओं से नशामुक्त पंजाब का सपना साकार नहीं होगा। सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि नशे की आपूर्ति कितनी घटी, कितने युवा उपचार के बाद सामान्य जीवन में लौटे और बड़े तस्करों तथा उनके संरक्षकों के विरुद्ध कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई।

नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक, सीमा सुरक्षा और वित्तीय जांच के साथ–साथ नशामुक्ति केंद्रों, मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोजगार और पुनर्वास पर भी समान ध्यान देना होगा। नशे के शिकार युवाओं को केवल अपराधी मानकर खारिज करना समाधान नहीं है, उन्हें उपचार, सहारा और सम्मानजनक जीवन में लौटने का अवसर देना भी जरूरी है। गांवों में जनभागीदारी, स्कूल–कॉलेजों में जागरूकता और परिवारों की सक्रिय भूमिका इस अभियान को जनांदोलन का स्वरूप दे सकती है। साथ ही, पुलिस और राजनीतिक तंत्र में किसी भी स्तर पर संरक्षण देने वालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंजाब को नशे की गिरफ्त से निकालना केवल सरकार का नहीं, पूरे समाज का दायित्व है, लेकिन नेतृत्व की पहली जवाबदेही सरकार की ही है। जब कानून के रखवाले ही संदेह के घेरे में आने लगें और करोड़ों की हेरोइन की बरामदगी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करे, तब आत्ममंथन टालना आत्मघाती होगा। 'लकीर पीटने' के बजाय अब निर्णायक परिणाम देने का समय है। पंजाब को खोखले नारों नहीं, कठोर कार्रवाई, पारदर्शी जांच और जवाबदेह शासन की जरूरत है। नशा माफिया की जड़ें उखाड़ने के लिए राजनीतिक संरक्षण की दीवारें तोड़नी होंगी और कानून का भय हर अपराधी तक पहुंचाना होगा। अन्यथा नशे का यह तांडव पंजाब की युवा शक्ति को ही नहीं, देश की सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर क्षति पहुंचाता रहेगा।

भोजन की बर्बादी से निपटने की वैश्विक चुनौती?

डॉ. रमेश ठाकुर

भोजन मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा, प्रत्येक इंसान का बुनियादी अधिकार भी है। भोजन अनमोल है जिसका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। आज 'विश्व खाद्य दिवस' है जो सालाना 16 अक्टूबर को पूरे संसार में इस मकसद से मनाया जाता है कि अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए जनमानस को जागरूक किया जाए। नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट् के खाद्य एवं कृषि संगठन के 20वें सम्मेलन में खाद्य दिवस को मनाने का निर्णय हुआ जिसका पहली बार आयोजन वर्ष 1981 में हुआ। दुनिया में भूख से बढ़ते कुपोषण पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक संघों को चेताया था। ये दिवस इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि हमें थाली में उतना ही भोजन परोसना चाहिए, जितने की पेट को जरूरत हो। ज्यादा भोजन लेंगे तो निश्चित रूप से बर्बाद ही होगा। फूड इंडेक्स पर यूएनईपी–2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सालाना करीब 7.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है, जिसका औसत लगभग 21.4 करोड़ किलोग्राम प्रतिदिन आंका गया। विश्व खाद दिवस–2025 की थीम थी 'बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ–साथ' जो एग्रीफूड सिस्टम को बदलने में वैश्विक सहयोग की शक्ति को उजागर करती है।

भोजन बर्बादी की समस्या संसार में बड़ी आफत के रूप में उभरी है। ऐसे तमाम मुल्क हैं जहां अन्न का उत्पादन शून्य है और दूसरे देशों के उत्पाद–भोजन पर ही निर्भर हैं, बावजूद इसके बेहताशा भोजन बर्बाद करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण

की 'फूडवेस्टाइज इंडेक्स रिपोर्ट–2026' सामने आई जिसमें दुनिया भर में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद होता बताया गया जिससे नई किस्म की न सिर्फ बीमारियां–वायरस फैले, बल्कि पर्यावरण भी दूषित हुआ। भारत में पिछले 10 वर्षों में अन्न उत्पादन 90 मिलियन मीट्रिक टन पिछले एक दशक से ज्यादा हुआ है। धरती पर मात्र भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो करीब 76 देशों को विभिन्न किस्म का अन्न सप्लाई करता है जिसमें चीनी, दालें, चावल, मखाने, सरसों और सब्जियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो भारत में उत्पादित बासमती चावल ही पसंद करते हैं। ईरान–ईराक में चावल की सप्लाई सिर्फ भारत से ही होती है। अन्न निर्यात के लिहाज से भारत विश्व का बड़ा बाजार बनकर इस समय उभरा है। संसार में भारत दूध और बाजरे के निर्माण में नंबर वन पायदान है। वर्ष 2014 के बाद से हिंदुस्तान शहद, अंडे, मछलियां और फल–सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर काबिज हुआ है। जबकि, कभी चौथे स्थान पर हुआ करता था।

भूखे सोना विकसित संसार के माथे पर कलंक जैसा है। भूख के आंकड़े आज भी डरावने हैं। संसार का एक बड़ा इंसानी हिस्सा अभी भी रात में भूखे पेट सोता है। जबकि, रोजाना जितनी भोजन की बर्बादी होती है, थालियों में खाने को व्यर्थ करके लोग फेंक देते हैं, अगर ऐसा ना किया जाए, तो भूखे सोने वालों के आंकड़ों में कमी लाई जा सकती है।

भोजन की बर्बादी से न केवल अन्न और धन का नुकसान होता है, बल्कि पानी, बिजली और अन्नदाताओं की सालाना मेहनत भी बेकार होती है। इससे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भूख से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी देशों को चेताना होगा। भूख और अन्न बर्बादी के नियंत्रण पर भारत जैसी पहल अन्य देशों को भी करनी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम पोषण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राइस फोर्टिफिकेशन और प्राइस स्थेबिलाइजेशन फंड जैसी प्रमुख पहले भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रही हैं। भारत में 80 करोड़ लोग मुफत अन्न वितरण योजना के लाभार्थी हैं, इसलिए सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोए। लेकिन भोजन की बर्बादी भारत में भी कम नहीं है। आंकड़े इस समस्या के गवाह हैं।

विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना का प्रतीक है जिसे पहली बार औपचारिक रूप से 1981 में 'भोजन सर्वप्रथम' विषय वस्तु के साथ मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1984 में इस दिवस को मान्यता दी जिसके बाद एक साथ 150 देशों का समूह बना, जो सामूहिक प्रयासों से भूख और अन्न बर्बादी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि, सफलता उतनी नहीं मिली, जितनी उम्मीदें लगाई गईं थीं। बहरहाल, आज का दिन खाद्य सुरक्षा, पोषण टिकाऊ, कृषि पद्धतियों के विषय में ना सिर्फ जागरूक करता है, बल्कि सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की सीख भी देता है। भोजन मानव जीवन का आधार है। स्वास्थ्य विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक भी। हालांकि, दुख तब होता है जब खाद्य उत्पादन में वैश्विक प्रगति के बाद भी असंख्य लोग अभी भी भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। भोजन पर सभी का मौलिक अधिकार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। भोजन हीन इंसान को भोजन उपलब्ध करवाना प्रत्येक हुकूमत का पहला कर्तव्य होता है।

Created by Universal Document Converter

परोआ में मेटाडोर के खाई में गिरने से 18 घायल

उधमपुर, 16 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। उधमपुर से परोआ जा रही एक मेटाडोर के धनाल के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से उसमें सवार 18 यात्री घायल हो गए।

जानकारी अनुसार गत देर शाम को उधमपुर से परोआ जा रही एक मैटाडोर नंबर (जे.के.14,सी–2791) जैसे ही धनाल के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे मेटाडोर खाई में जा गिरी। इससे वहां पर हाहाकार मच गया। वहीं स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी लगते ही उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी तथा खुद राहत कार्य में जुट गए। घायलों को बाहर निकाला गया तथा उन्हें जीएमसी उधमपुर में शिफ्ट किया गया।

हादसे में घायल हुए यात्रियों की पहचान

इस दुर्घटना में 18 यात्री घायल हुए जिनकी पहचान अनु देवी पुत्री गोविंद राम, गायत्री देवी पत्नी स्व.बद्रीनाथ, शीलो देवी पत्नी संजय कुमार, ओम प्रकाश पुत्र मंगत राम, दर्शन कुमार पुत्र बंसी लाल, अशोक पुत्र चेत राम, सुदेश पुत्र काका राम, मनीषा शर्मा पत्नी कृष्ण कुमार, सोहन पुत्र शाम लाल, अनिल पुत्र देस राज, ज्योति पत्नी दर्शन कुमार, काज पत्नी दीपक, अभिषेक पुत्र नारायण दत्त, आरूष पुत्र दर्शन, मीनाक्षी पत्नी सुनील कुमार, हरी दत्त पुत्र ओम प्रकाश, जोगेंद्र पुत्र ओम प्रकाश, अजय पुत्र काका राम के रूप में की गई है।

घायलों का हालचाल जानने पहुंचे विभिन्न पार्टियों के नेता

इस हादसे की जानकारी मिलने के उपरांत वरिष्ठ नेता पवन खजूरिया, पूर्व विधायक एवं मंत्री हर्ष देव सिंह व चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया घायलों का हालच. ाल जानने जीएमसी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बात की घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

अम्फल्ला-जानीपुर मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में सुनील डिंपल ने निकाली रैली

जम्मू। मिशन स्टेटहुड जम्मू–कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने अम्फल्ला–जानीपुर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में रैली निकाली। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस परियोजना को रोकने पर विचार नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डिंपल ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण की चर्चाओं से व्यापारियों और स्थानीय निवा. सियों में चिंता है। उन्होंने दावा किया कि दुकानों, शोरूमों और रिहायशी मकानों की कीमतें गिर रही है तथा लोगों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा है। उन्होंने सरकार से परियोजना का पूरा नक्शा सार्वजनिक करने और प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की योजना स्पष्ट करने की मांग की।

डिंपल ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से फ्लाईओवर परियोजना रोककर अम्फल्ला से अखनूर तक रिंग रोड तथा मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन में कई व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नेता शामिल हुए।

डीसी अनंत द्विवेदी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और देविका घाट का किया दौरा

चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण

उधमपुर, 16 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। उधमपुर के उपायुक्त अनंत द्विवेदी ने सुई क्षेत्र का दौरा किया तथा वहां पर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट–3 का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा–निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने देविका स्थित श्मशान घाट का दौरा किया तथा वहां पर निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के कार्य की प्रगति का आकलन किया।

इस दौरान डीसी ने संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य में तेजी लाने, निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता मानक. ों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

ऊधमपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल अंडर–19 गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज

विभिन्न जिलों की 18 टीमें ले रही हैं प्रतियोगिता में भाग

उधमपुर, 16 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। मिनी स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक प्रदेश स्तरीय अंडर–19 लड़कियों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें जम्मू–कश्मीर के

विभिन्न जिलों की अंडर–19 वर्ग की लड़कियां की 18 टीमें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

यह टूर्नामेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, ऊधमपुर और मिनी स्टेडियम ऊधमपुर में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करना और खेलों के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देना है। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला आयुक्त अनंत द्विवेदी द्वारा किया गया।

इस आयोजन का संचालन जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय, ऊधमपुर द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने, प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल करने और भविष्य में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने का अवसर मिलेगा।

मां भगवती के जागरण में कलाकारों ने हिस्सा लेकर मां भगवती का किया गुणगान

आरएस पुरा। आरएस पुरा क्षेत्र के गांव चौहाला में गुरुवार रात्रि को मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर

के साथ–साथ अन्य राज्यों से पहुंचे हुए प्रसिद्ध गायको ने अपनी मधुर आवाज के साथ मां भगवती का गुणगान किया। इस मौके पर थाना प्रभारी आरएस पुरा विक्रम सिंह चिब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे जिन्होंने पंचायत के पूर्व सरपंच अशोक कुमार, पूर्व पंच जनक राज तथा जागरण कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में मां भगवती की पवित्र ज्योत प्रज्वलित कर इस भव्य जागरण की शुरुआत करवाई। इसके उपरांत जागरण कमेटी की तरफ से आए हुए अतिथियों को माता रानी की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्थानीय कलाकार अश्विनी कुमार के साथ–साथ अन्य कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज से मां भगवती का गुणगान किया। इस मौके पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चिब ने सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रों की मुबारकबाद देते हुए कहा कि माता रानी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने इस मौके पर नौजवान पीढ़ी से अपील करते हुए कहा कि वह समाज की भलाई में अपना योगदान दें। इस मौके पर पूर्व सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि पवित्र नवरात्रों पर हर वर्ष गांव में माता रानी के भव्य जागरण का आयोजन करवाया जाता है जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ–साथ अन्य राज्यों के भी प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेकर मां भगवती का गुणगान करते है। उन्होंने इस मौके पर गांव में विशाल जागरण आयोजित करवाने के लिए जागरण कमेटी के सदस्यों की भी प्रशंसा की। इस मौके पर जागरण कमेटी के सदस्य शिशुपाल मोटन, रवि कैथ, यश कैथ, बाबा राम कैथ, सेठी कैथ, सूरज कैथ, मनु कैथ, राहुल कैथ तथा अमित कैथ सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

पंजाबी भाषा को जम्मू–कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के आश्वासन पर सिख संगत ने जताया आभार

जम्मू। जम्मू की सिख संगत ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में पंजाबी भाषा को आधिक. ारिक भाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने के आश्वासन का स्वागत करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस प्रस्ताव में गोजरी और पहाड़ी भाषाओं को शामिल करने का भी आश्वासन दिया गया है।

नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सांसद शम्मी ओबराय द्वारा दिए गए आश्वा. सन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सिख समुदाय में खुशी की लहर है। गांधी नगर स्थित पार्टी के प्रांतीय मुख्यालय में जम्मू के विभिन्न गुरुद्वारों की प्रबंधक समितियों के अध्यक्षों और अन्य प्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया।

गुप्ता ने कहा कि सिख समुदाय लंबे समय से पंजाबी भाषा को उचित मान्यता और

प्रोत्साहन देने की मांग करता आ रहा है। पंजाबी भाषा समृद्ध साहित्यिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और जम्मू–कश्मीर में सिख समुदाय के ऐतिहासिक योगदान का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाएंगे और पंजाबी भाषी लोगा. ें की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाषाई विविधता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। जम्मू–कश्मीर की बहुसांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए सभी भाषाओं और समुदायों को समान सम्मान मिलना आवश्यक है।

गुप्ता ने कहा कि डा. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सिख समुदाय तथा सिख धर्म के प्रति विशेष लगाव और सम्मान रहा है। इस अवसर पर शेख बशीर अहमद, दीपिंदर कौर, राकेश सिंह राका, दिलशाद मलिक, सरदार संदीप सिंह वजीर, सुभाष भगत, सरदार सेवक सिंह, सरदार गुरनाम सिंह, पिंकी खालसा सहित नेशनल कान्फ्रेंस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शोक सभा आयोजित

पूर्व प्रदेश मंत्री सरदार हरबंस सिंह के निधन पर जताया शोक

उधमपुर, 16 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। समाज सेवक विपिन दुबे की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश मंत्री सरदार हरबंस सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरदार हरबंस सिंह के निधन से न सिर्फ पार्टी का एक वरिष्ठ नेता चला गया, बल्कि एक गरीबों का मसीहा चला गया है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

शोक सभा में कृष्ण सिंह, ओम प्रकाश, रामलाल, सूरज प्रकाश, राधेश्याम, संतोष लाल आदि उपस्थित थे।

पंचौरी में भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल

प्राथमिक उपचार के उपरांत जीएमसी उधमपुर रेफर

उधमपुर, 16 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। मानव वन्यजीव संघर्ष की एक और भयावह

घटना में, उधमपुर जिले की पंचौरी तहसील के नल्लियां क्षेत्र में एक जंगली भालू के हमले में 29 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता की पहचान कमलेश देवी पत्नी संजय कुमार निवासी चुलना, नल्लियां के रूप में हुई है।

स्थानीय वासियों के अनुसार पीड़िता पर अचानक भालू द्वारा हमला किया गया। पीड़िता की चीखें सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उसे भालू से बचाया। महिला को पहले प्राथमिक उपचार के लिए पंचौरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चोटों की गंभीरता और अत्यधिक खून बहने को देखते हुए, उपस्थित डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जीएमसी रेफर कर दिया।

पंचौरी तहसील में बार–बार हो रहे भालू के हमलों ने स्थानीय निवासियों में व्यापक भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने वन्यजीव संरक्षण विभाग और जिला प्रशासन से अपील की है कि वे भालू को पकड़ने के लिए तुरंत ट्रैकिंग टीमें तैनात करें और आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गश्त तेज करें।

अमित कपूर ने उठाई आईएएस कुमार राजीव रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग

जम्मू। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, एक वायरल वीडियो में उन्हें एक आधिकारिक वर्चुअल मीटिंग के दौरान, प्रांतीय सेवा की एक महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा कि रंजन का तुरंत तबा. दला कर दिया जाना चाहिए और उनके आचरण की औपचारिक जांच पूरी होने तक उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए।

बताते चलें कि मिशन युवा पर आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान, रंजन और सहायक निदेशक बीनीश वानी के बीच नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की भूमिका को लेकर तीखी बहस हुई। इस घटना का पता एक कथित वीडियो से चला। उन्होंने वानी के साथ हुई कथित बदसलूकी और सबके सामने उनके अपमान की निंदा की और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि वे प्रशास. निक जवाबदेही और कामक. ाज की निगरानी का पूरा समर्थन करते है, लेकिन उनका मानना है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अभद्र भाषा के इस्तेमाल, डराने–धमकाने या ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकता, जो किसी कार्यरत अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो।

जेकेएएस अधिकारी के कथित अपमान की हकीम यासीन ने की निंदा, निष्पक्ष जांच की मांग

जम्मू/श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने एक आधिका. रिक बैठक के दौरान वरिष्ठ जेकेएएस अधिकारी के साथ आईएएस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

यासीन ने कहा कि यह घटना स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के पुनर्गठन के बाद उत्पन्न प्रशासनिक असंतुलन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए है। यासीन के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानीय कैडर के अधिकारियों की तुलना में अधिक अधिकार मिल रहे है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी का अपमान स्वीकार्य नहीं है और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

Created by Universal Document Converter

बिजली दरों में बढ़ोतरी व्यापार और उद्योग के लिए चिंता का विषयः अनिल गुप्ता

जम्मू। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने जम्मू–कश्मीर में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से संशोधित दरों की समीक्षा करने और व्यापारिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की मांग की है।

अनिल गुप्ता ने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि से औद्योगिक इकाइयों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिचालन लागत बढ़ गई है। ये उद्योग पहले ही कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, परिवहन खर्च और दूसरे राज्यों के उद्योगों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली महंगी होने से उद्योगों के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होने, नए निवेश में कमी आने और रोजगार के अवसर प्रभावित होने की आशंका है। गुप्ता ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि बिजली की संशोधित दरों पर पुनर्विचार कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उचित राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर में मौजूदा उद्योगों की सुरक्षा, नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सस्ती बिजली तथा अनुकूल कारोबारी माहौल बेहद आवश्यक है।

उन्होंने जोर दिया कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र को राहत देकर ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति दी जा सकती है और औद्योगिक विकास को मजबूत बनाया जा सकता है।

अखनूर रामलीला में 40 सालों से राम बने आ रहे हैं वरिंदर मिश्रा

अखनूर। श्री रामलीला क्लब अखनूर द्वारा अध्यक्ष राजीव शर्मा और प्रधान बृजपाल मेहता की अध्यक्षता में मिडिल स्कूल अखनूर में चल रही रामलीला में आस्था और समर्पण की एक मिसाल देखने को मिल रही है।

क्लब में वरिंदर मिश्रा पिछले 40 सालों से लगातार भगवान श्री राम जी की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ कमल मेहता पिछले 20 सालों से लक्ष्मण जी की भूमिका में और सीता जी की भूमिका प्रिंस परिवार द्वारा पिछले 10 सालों से निभाई जा रही है।

इस मौके पर वरिंदर मिश्रा ने कहा कि मेरी उम्र 70 वर्ष से भी ज्यादा हो चुकी है, इसके बावजूद मैं आज भी श्री राम जी के आशीर्वाद से यह भूमिका निभा रहा हूं। यह सब राम जी की कृपा है जो मैं इतने सालों से यह भूमिका निभाता आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस पात्र को निभाने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है, शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना पड़ता है।

वहीं इस बार की रामलीला में राबिया खजूरिया ने अपनी कला से चार चांद लगा दिए हैं। उन्होंने राम की लीला में शबरी की भूमिका निभाकर अपने भावपूर्ण अभिनय से लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। शबरी–राम मिलन के दृश्य ने सभी को भावुक कर दिया। क्लब के महामंत्री मोहन सिंह जम्वाल कहा कि इस बार की रामलीला में युवा वर्ग की अहम भूमिका रही है, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है और सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।

बड़गाम–कटड़ा स्पेशल ट्रेन अब नए नंबर से चलेगी, 19 अक्टूबर से होगा बदलाव

जम्मू। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़गाम–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–बड़गाम स्पेशल ट्रेन के नंबर में बदलाव किया है। 19 अक्टूबर से यह ट्रेन अपने पुराने नंबर 04688/04687 के स्थान पर नए नियमित नंबर 14688/14687 से एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित होगी।

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14688 बड़गाम से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और ट्रेन संख्या 14687 कटड़ा से बड़गाम के बीच चलेगी। इस बदलाव के तहत केवल ट्रेन नंबर बदला गया है, जबकि ट्रेन के समय, ठहराव, कोच संरचना और मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे 19 अक्टूबर से यात्रा की योजना बनाते समय नए ट्रेन नंबर का ध्यान रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यात्री ट्रेन के समय और अन्य परिचालन संबंधी जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

भजन चंडी मां दे जाना' का विमोचन, तरुण उप्पल ने खुशाल बनोत्रा को दी बधाई

जम्मू। जम्मू की धार्मिक आस्था और डुग्गर संस्कृति को समर्पित युवा गायक खुशाल बनोत्रा के भक्तिमय भजन 'चंडी मां दे जाना' का विमोचन तालाब तिल्लो स्थित निर्भय भारत फाउंडेशन के कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के चेयरमैन तरुण उप्पल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त निदेशक विजिलेंस रोमेश चंदर, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी के चेयरमैन माणिक उप्पल, मास्टर राहुल और पंडित विशाल भी मौजूद रहे। तरुण उप्पल ने खुशाल बनोत्रा और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि संगीत जम्मू–कश्मीर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उचित मंच प्रदान करने पर जोर दिया। भजन का संगीत नरेश कंठ ने तैयार किया है, जबकि बोल साहिल शर्मा साहू ने लिखे हैं। वीडियो का निर्देशन अजय ठाकुर ने किया है। यह भजन दुग्गर हिल्स प्रोडक्शन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने श्रीनगर में समुदाय की मदद के लिए कंबल वितरण अभियान किया आयोजित

श्रीनगर (तारिक मीर)। ठंड के मौसम में ज़रूरतमंद समुदायों की मदद करने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाते हुए, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने कश्मीर के डाउनटाउन श्रीनगर में एक कंबल वितरण अभियान आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों और परिवारों को गर्माहट और राहत पहुँचाना था, जो मानवीय कार्यों और सामुदायिक कल्याण के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को फिर से दर्शाता है।

इस पहल के तहत, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की संस्थापक रूबल नागी ने समुदाय के लोगों के बीच कंबल बाँटने के काम का नेतृत्व किया। 'इस कंबल वितरण अभियान में 150 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया'। यह अभियान उन लोगों और परिवारों की मदद के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें सर्दियों के मौसम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ताकि उन्हें ज़रूरी गर्माहट और देखभाल मिल सके।

यह पहल उन समुदायों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है, जहाँ तक अक्सर मदद नहीं पहुँच पाती। सर्दियों के लिए ज़रूरी सामान उपलब्ध कराकर, आरएनएएफ लोगों को सहारा देने के साथ–साथ सम्मान, करुणा और सामाजिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहता है।

इस पहल के ज़रिए, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद समुदायों तक पहुँचने और यह सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों को मानवीय सहायता मिल सके। श्रीनगर में आयोजित यह कंबल वितरण अभियान, समुदाय–केंद्रित पहलों के ज़रिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के आरएनएएफ के व्यापक मिशन को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आया जाए और ज़रूरत के समय उसे ज़रूरी मदद मिले।

पंजाबी को आधिकारिक दर्जे के लिए केंद्र से मिले लिखित गारंटीः शिवसेना

पंजाबी भाइयों को जीत की बधाई, उमर सरकार के आश्वासन का स्वागतः साहनी

जम्मू। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू–कश्मीर इकाई ने पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे पंजाबी भाइयों को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए उनके संघर्ष की सराहना की है। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा 2027 के बजट सत्र में पंजाबी भाषा से संबंधित विधेयक लाने के आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन केंद्र सरकार से भी लिखित गारंटी देने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पंजाबी भाइयों ने अपनी मां–बोली के सम्मान के लिए जिस एकजुटता, धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, वह बधाई के पात्र हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार का आश्वासन सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाबी को आधिकारिक दर्जा देने का फैसला केवल जम्मू–कश्मीर सरकार के अधिकार क्षेत्र में है? जब संबंधित कानून संसद द्वारा पारित किया गया है, तो इस मांग को कानूनी रूप देने के लिए केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता भी जरूरी है।

साहनी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा कई बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ। कहीं हमारी मां–बोली पंजाबी के साथ भी ऐसा ही न हो जाए और समुदाय को आश्वासनों के इंतजार में वर्षों न बिताने पड़ें।

उन्होंने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से पंजाबी को आधिकारिक दर्जा देने के लिए स्पष्ट समयसीमा के साथ लिखित आश्वासन देने की अपील की। ताकि भविष्य में पंजाबी भाषा और उसके समर्थकों के साथ कोई अन्याय न हो। साहनी ने कहा कि जहाँ डोगरी हमारी शान, पंजाबी हमारी साझा विरासत है। शिवसेना पंजाबी समुदाय के संघर्ष के साथ खड़ी है और चाहती है कि उसकी जीत स्थायी, कानूनी और निर्णायक बने।

उरी में भारतीय सेना ने लगाया कृत्रिम अंग शिविर, 243 लाभार्थियों को मिले सहायक उपकरण

उरी। भारतीय सेना की कालापहाड़ ब्रिगेड के तत्वावधान में बजरंग बटालियन ने 14 से 16 अक्टूबर तक उरी में तीन दिवसीय कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन, पुंछ और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर फुट) के सहयोग से आयोजित इस शिविर में दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए।

शिविर का उद्घाटन कालापहाड़ ब्रिगेड के कमांडर ने स्थानीय नागरिक समाज के सदस्यों की उपस्थिति में किया। इसका उद्देश्य उरी और बोनियार तहसीलों के दूरदराज सीमावर्ती गांवों में रहने वाले दिव्यांगजनों को बेहतर गतिशीलता, आत्मविश्वास और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना था।

शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रोस्थेटिक तकनीशियनों और सहयोगी कर्मचारियों की टीम ने कुल 243 लाभार्थियों की जांच कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए। लाभार्थियों को कृत्रिम अंगों के उपयोग के लिए चलने का प्रशिक्षण और आवश्यक परामर्श भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, 43 लाभार्थियों को व्हीलचेयर प्रदान की गई, जबकि 76 लोगों की सुनने की क्षमता की जांच कर उन्हें निःशुल्क हियरिंग एड दिए गए।

स्थानीय लोगों ने सेना की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारतीय सेना की इस पहल ने सेवा, समावेशिता और जनकल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। साथ ही, इसने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और आम जनता के बीच विश्वास एवं सहयोग के संबंधों को और मजबूत किया।

एनआईटी श्रीनगर में टिकाऊ धातु विज्ञान और हरित ऊर्जा परिवर्तन पर कार्यक्रम आयोजित

श्रीनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) श्रीनगर की एलुमनाई एसोसिएशन ने डीन ऑफ एलुमनाई एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के सहयोग से 'एलुमनाई बैक टू कैंपस' कार्यक्रम आयोजित किया। हाई–टेक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल मैटेरियल्स के प्रोजेक्ट ग्रुप लीडर और संस्थान के पूर्व छात्र डॉ. इंजीनियर उबैद मंजूर ने विद्यार्थियों के साथ अपने शोध अनुभव साझा किए।

डॉ. मंजूर ने कहा कि हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए धातुओं और सामग्रियों के उत्पादन में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक बुनियादी ढांचे में निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि पारंपरिक तरीके से एक टन निकल के उत्पादन में लगभग 22 से 28 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो सकती है। उन्होंने हाइड्रोजन प्लाज्मा स्मेल्टिंग रिडक्शन तकनीक को पारंपरिक कार्बन–आधारित प्रक्रियाओं का संभावित विकल्प बताया। डीन एम. ए. शाह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को उन्नत शोध और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में वैज्ञानिक नवाचार की भूमिका समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

सांबा बस स्टैंड की नान दुकान में युवक मृत मिला, मौके पर पहुंची पुलिस

सांबा (निखिल पंगोत्रा)। सांबा बस स्टैंड के मुख्य चौक के समीप शुक्रवार सुबह एक नान की दुकान के भीतर व्यक्ति के मृत मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करीब 34–35 वर्षीय रवि कुमार, निवासी गांव नगरोटा, सांबा के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार रवि कुमार उक्त दुकान पर काम करता था। शुक्रवार सुबह काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। जब दुकान के अंदर जाकर देखा गया तो रवि कुमार मृत अवस्था में मिला। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल रवि कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी

पहलुओं की जांच कर रही है और आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। घटना की खबर फैलते ही बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस जांच जारी है और अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही मामले की पूरी

नेकां सरकार के बहाने टूटे वादों को छिपा नहीं सकतेः रमन सूरी

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन सूरी ने नेशनल कांफ्रेंस सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा न करके और शक्तियों की कमी का बहाना बनाकर जम्मू–कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है। अपने दो साल पूरे होने पर नेकां के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, यही वजह है कि सरकार ने अपनी प्रगति पर चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा।

सूरी ने कहा कि नेकां सरकार अपने वादों को पूरा न करके लोगों का समय बर्बाद कर रही है। जवाबदेही तय करने के बजाय, वे अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने का तरीका है। उन्होंने बताया कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा अब केवल अंत्योदय अन्न योजना परिवारों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे बाकी अधिकांश लोग इससे वंचित रह गए हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बजाय, उन्हें बिजली की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।

सूरी ने सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि बार–बार किए गए वादों के बावजूद, 61,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था लेकिन इसके बजाय सरकार ने नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया जिससे उन लोगों को धोखा मिला जिन्होंने सरकार की बातों पर भरोसा किया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन

का यह दावा कि उनके पास सीमित शक्तियां हैं, पूरी तरह खोखला है। शासन का मतलब काम करके दिखाना है, न कि बहाने बनाना। नेकां सरकार का अपने ही घोषणापत्र पर अमल न कर पाना यह दिखाता है कि उनमें काम करने की इच्छाशक्ति की कमी है, न कि शक्तियों की।

रमन सूरी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की जनता को एक ऐसी सरकार चाहिए जो अपने वादे पूरे करे, न कि ऐसी सरकार जो बहानों की आड़ ले। नेकां सरकार को जनता को गुमराह करना बंद करना चाहिए और उनके लिए काम करना शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव न कराकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित कर ली हैं और लोगों को उनकी पंचायतों के जरिए निर्णय लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं।

जब से मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू–कश्मीर सरकार की कमान संभाली है, तब से वे लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का राग अलाप रहे हैं और इसी मांग की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। यह जानते हुए कि राज्य का दर्जा मिलने का विकास या लोगों को एक जवाबदेह सरकार देने से कोई लेना–देना नहीं है, वे इस मांग की आड़ ले रहे हैं, एक ऐसी मांग जिसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन सही समय आने पर इसे पूरा किया जाएगा। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपने दो साल के शासन का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें ताकि लोग खुद यह देख सकें कि चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में वे कहां तक पहुंचे हैं।

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए सांसद जुगल किशोर शर्मा से मिले एसबीआईओए प्रतिनिधि

जम्मू। स्टेट बैंक आफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, जम्मू माड्यूल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सांसद जुगल किशोर शर्मा से उनके जम्मू स्थित आवास पर मुलाकात कर बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बैंकों में शेष दो शनिवारों को भी अवकाश घोषित किया जाए जिससे देशभर के लगभग 20 लाख बैंक कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सके। एसबीआईओए जम्मू माड्यूल के उपमहासचिव राजेश मेहता ने कहा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बैंक यूनियनें सप्ताह के अन्य कार्यदिवसों में काम के घंटे बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि कुल कार्य घंटों में कमी न आए। डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और अन्य आनलाइन सेवाएं भी जारी रहेंगी।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारतीय बैंक संघ ने जुलाई 2023 में सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। मार्च 2024 के समझौते में भी इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष मामला उठाने तथा संसद में इसके शीघ्र निर्णय और कार्यान्वयन की समयसीमा तय करवाने का आग्रह किया।

Created by Universal Document Converter

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम: संघर्ष से शिखर तक, विज्ञान से राष्ट्र निर्माण तक की प्रेरक यात्रा

विश्वनाथ झा

"सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते" इस दर्शन को जीवंत करने वाले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आधुनिक भारत के एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनका संपूर्ण जीवन सादगी, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति की मिसाल है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने सिद्ध किया कि अभाव और सीमित संसाधन कभी प्रतिभा की सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकते। वे वैज्ञानिक की तीक्ष्ण बुद्धि, दार्शनिक के चिंतन, शिक्षक के पावन हृदय और देशभक्ति के संकल्प का अद्भुत संगम थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व ने देश को सामरिक व वैज्ञानिक संप्रभुता प्रदान की। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को नई ऊंचाइयां दीं। 'जनता के राष्ट्रपति' बनकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार आम नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों के ज्ञान, चरित्र और रचनात्मक संकल्प में निहित है। जीवन की अंतिम सांस तक युवाओं को 'विकसित भारत' का स्वप्न साकार करने के लिए प्रेरित करने वाले डॉ. कलाम अपने विचारों और आदर्शों का ऐसा दीप प्रज्वलित कर गए, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उनका जीवन केवल एक वैज्ञानिक की असाधारण उपलब्धियों की गाथा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित एक कर्मयोगी की अमर प्रेरणा कथा है।

रामेश्वरम से शुरू हुई संघर्ष और संकल्प की यात्रा

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव से संबंधित व्यवसाय करते थे और स्थानीय समाज में सम्मानित थे, जबकि माता आशियम्मा स्नेहशील तथा उदार स्वभाव की थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन ईमानदारी, अनुशासन, धार्मिक आस्था और परोपकार जैसे संस्कार जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। रामेश्वरम का बहुधार्मिक सामाजिक वातावरण उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा। विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सद्भाव और सहयोग ने उनके भीतर धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। इन संस्कारों की झलक उनके निजी और सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देती रही। बचपन से ही उन्होंने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए पढ़ाई के साथ समाचार पत्र वितरण में हाथ बंटाया। इस अनुभव ने उनमें परिश्रम, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। शिक्षा के प्रति उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। शिक्षकों ने भी उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया और प्रकृति तथा आसपास की दुनिया को समझने की प्रेरणा दी। रामेश्वरम में बिताए गए शुरुआती वर्षों ने उनके व्यक्तित्व की मजबूत नींव रखी, जिसने आगे चलकर उन्हें देश के अग्रणी वैज्ञानिकों और प्रेरणादायी राष्ट्र निर्माताओं में स्थान दिलाया।

शिक्षा ने दिखाई सफलता की राह

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की शैक्षिक यात्रा उनकी जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और निरंतर सीखने की ललक का प्रमाण है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त की। इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। विमानन के क्षेत्र में काम करने की आकांक्षा ने उन्हें तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया, जिसने उनके वैज्ञानिक करियर की मजबूत नींव रखी। इस दौरान उन्होंने समझा कि किसी विचार को साकार करने के लिए प्रतिभा के साथ अनुशासन, अभ्यास, समय–प्रबंधन और समस्या समाधान की क्षमता भी आवश्यक है। उनके लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि देश की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्र सेवा में योगदान देने का माध्यम थी। यही दृष्टिकोण उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर ले गया। डॉ. कलाम का जीवन विद्यार्थियों को संदेश देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना या डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन, नवाचार और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना है। उन्होंने ज्ञान को आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया।

वैज्ञानिक जीवन और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने रक्षा और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करते हुए तकनीकी चुनौतियों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की जटिलताओं का अनुभव प्राप्त किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से जुड़े, जहां उन्हें भारत की स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता विकसित करने में योगदान देने का अवसर मिला। इसरो में डॉ. कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल–3 (एसएलवी–3) परियोजना के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1980 में एसएलवी–3 की सहायता से रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई और देश की स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को मजबूती मिली। इस सफलता के पीछे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों का सामूहिक प्रयास था। डॉ. कलाम टीम भावना, निरंतर प्रयोग और असफलताओं से सीखने को वैज्ञानिक प्रगति का आवश्यक आधार मानते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक प्रयोग भविष्य की उपलब्धियों के लिए नया अनुभव प्रदान करता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान ने साबित किया कि तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दूरदर्शी योजना, निरंतर अनुसंधान और संस्थागत सहयोग आवश्यक हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद स्वदेशी तकनीक विकसित करने की यह प्रतिबद्धता भारत की वैज्ञानिक यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय बनी।

मिसाइल विकास और 'मिसाइल मैन' की पहचान

भारतीय रक्षा अनुसंधान में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान ने उन्हें देश–विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाई। वर्ष 1980 के दशक में उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के प्रमुख के रूप में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रणालियों के विकास में उनके योगदान के साथ आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी प्रणालियों ने भी इस कार्यक्रम को व्यापक बनाया। रक्षा क्षेत्र में इन प्रयासों के कारण डॉ. कलाम को 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाने लगा। मिसाइल विकास जैसी जटिल परियोजनाओं में अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और तकनीकी सुधार के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के बीच समन्वय आवश्यक होता है। डॉ. कलाम ने अपने नेतृत्व और टीम भावना से इन प्रयासों को दिशा दी। वे स्वदेशी अनुसंधान और तकनीकी आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते थे। उनकी उपलब्धियां इसी दूरदर्शी सोच और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण हैं।

पोखरण परमाणु परीक्षण और सामरिक क्षमता

मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण भारत के सामरिक और वैज्ञानिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थे। उस समय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ इन परीक्षणों से संबंधित प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पोखरण परीक्षणों ने भारत की सामरिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इसके बाद देश की सुरक्षा नीति, परमाणु अप्रसार और वैश्विक कूटनीति को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस घटना को समझने के लिए इसके वैज्ञानिक महत्व के साथ राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इन परीक्षणों की सफलता अनेक वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, संस्थानों और सरकारी नेतृत्व के सामूहिक प्रयासों का परिणाम थी। डॉ. कलाम का योगदान इसी व्यापक राष्ट्रीय अभियान का अहम हिस्सा रहा। उनका वैज्ञानिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण निरंतर अनुसंधान, तकनीकी दक्षता और सामूहिक प्रतिबद्धता से होता है। साथ ही, सामरिक शक्ति के साथ शांति और जिम्मेदार नीति के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

विज्ञान का सामाजिक उपयोग और मानवीय संवेदना

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि वे तकनीक को मानव जीवन की बेहतरी का माध्यम मानते थे। उनके लिए अनुसंधान की सार्थकता तभी थी, जब उसका लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे। वे विज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में करना चाहते थे। हृदय रोगियों के लिए विकसित कलाम–राजू स्टेंट इसी सोच का उल्लेखनीय उदाहरण है। डॉ. कलाम और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. बी. सोमा राजू ने चिकित्सा तकनीक को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम किया। इसी तरह, दिव्यांग बच्चों के लिए हल्के कैलिपर्स बनाने में कार्बन–कंपोजिट तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे उनके लिए चलना–फिरना आसान बनाने में मदद मिली। इन प्रयासों ने दिखाया कि रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में विकसित तकनीक का उपयोग चिकित्सा तथा सामाजिक कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। डॉ. कलाम का यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। विज्ञान और नवाचार तभी व्यापक अर्थों में सफल हैं, जब वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और विकास की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें।

विजन 2020: विकसित भारत की परिकल्पना

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत वैज्ञानिक क्षमता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास के बल पर एक विकसित राष्ट्र बने। इस दृष्टि को व्यापक रूप देने के लिए उन्होंने वाईएस राजन के साथ **India 2020: A Vision for the New Millennium** पुस्तक लिखी। इसमें देश की विकास संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए कृषि, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संतुलित विकास पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि भारत को तकनीक के उपयोग तक सीमित रहने के बजाय अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए सरकार, उद्योगों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण विकास उनकी परिकल्पना का महत्वपूर्ण आधार था। उनकी **PURA** यानी **Providing Urban Amenities to Rural Areas** अवधारणा का उद्देश्य गांवों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना था। इसमें भौतिक संपर्क, संचार, ज्ञान तक पहुंच और आर्थिक गतिविधियों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना की गई। कलाम का विश्वास था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। विजन 2020 का निर्धारित वर्ष बीत चुका है, लेकिन इसके मूल विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण–शहरी अंतर कम करना विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कलाम के अनुसार, विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, समान अवसर और मजबूत संस्थागत व्यवस्था भी है।

राष्ट्रपति भवन में जनता के राष्ट्रपति

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का एक ऐतिहासिक पड़ाव वर्ष 2002 में आया, जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2002 को पदभार ग्रहण किया और 25 जुलाई 2007 तक इस दायित्व का निर्वहन किया। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना उनके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी सादगी, सहजता और आत्मीय व्यवहार से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों के प्रश्न सुनते और उन्हें विज्ञान, शिक्षा तथा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते थे। उनकी लोकप्रियता का आधार केवल राष्ट्रपति पद नहीं, बल्कि आम लोगों से उनका आत्मीय जुड़ाव था। इसी कारण वे 'जनता के राष्ट्रपति' के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ज्ञान, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी को राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास था कि देश का भविष्य नागरिकों की सोच, क्षमता और कर्मठता से आकार लेता है। राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद भी उन्होंने शिक्षण, लेखन और युवाओं से संवाद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अपने अभियान को जारी रखा।

शिक्षक, लेखक और युवाओं के प्रेरणास्रोत

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं को शिक्षक के रूप में देखना सबसे अधिक पसंद करते थे। राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद भी उन्होंने शिक्षण और अकादमिक गतिविधियों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाए रखा। वे अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में प्रोफेसर के रूप में जुड़े और देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों से संवाद करते रहे। उनका विश्वास था कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिलें, तो वे सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के प्रभावी वाहक बन सकते हैं। वे विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते थे। कलाम असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह जीवन में भी प्रत्येक प्रयास अनुभव प्रदान करता है। उनके अनुसार, सफलता के लिए इच्छाशक्ति के साथ ज्ञान, तैयारी, अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। उनकी आत्मकथा **Wings of Fire** यानी 'अग्नि की उड़ान' में बचपन, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा का वर्णन मिलता है। **Ignited Minds** में उन्होंने युवाओं की क्षमताओं और राष्ट्र निर्माण पर विचार व्यक्त किए, जबकि प्दकपं 2020 में विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की। **My Journey: Transforming Dreams into Actions** में उनके जीवन के प्रेरक अनुभव संकलित हैं। कलाम युवाओं को केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं देखना चाहते थे। वे उनमें नवाचार, समस्या समाधान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना चाहते थे। उनके लिए शिक्षक का वास्तविक दायित्व विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास, नैतिक विवेक और देश के प्रति प्रतिबद्धता जगाना था। यही दृष्टि उन्हें एक वैज्ञानिक के साथ–साथ एक प्रेरणादायी शिक्षक और मार्गदर्शक बनाती है।

सादगी, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्य

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ–साथ सादगी, विनम्रता और नैतिक मूल्यों के लिए भी याद किया जाता है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने सरल जीवन शैली बनाए रखी। अनुशासन, निरंतर सीखने की ललक और दूसरों के प्रति सम्मान उनके व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं थीं। रामेश्वरम में बिताए बचपन और पारिवारिक संस्कारों ने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया। वे विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते थे और मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार मानते थे। उनके व्यक्तित्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक चिंतन का संतुलित समन्वय दिखाई देता था। विज्ञान ने उन्हें तर्क, प्रयोग और प्रमाण का महत्व सिखाया, जबकि नैतिकता ने जिम्मेदारी और आत्मानुशासन की भावना को मजबूत किया। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में उनका दृष्टिकोण सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। वे व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ सामूहिक प्रयासों को भी महत्व देते थे तथा युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका जीवन सिखाता है कि ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ जिम्मेदारी और अधिकार के साथ सेवा–भाव भी आवश्यक है।

पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मान

डॉ. कलाम को उनके वैज्ञानिक योगदान और राष्ट्र सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कीं। इन सम्मानों ने उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी, लेकिन उनके जीवन का महत्व पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति समाज की रुचि बढ़ाने में भी योगदान दिया। उनकी यात्रा ने अनेक विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित किया तथा यह विश्वास मजबूत किया कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जा सकता है।

अंतिम क्षण तक विद्यार्थियों के बीच

27 जुलाई 2015 को डॉ. कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। जीवन के अंतिम दिन भी विद्यार्थियों के बीच उनकी उपस्थिति उनके व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती है। शिक्षण उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने का माध्यम था। उनके निधन से देश ने एक महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, लेखक और प्रेरक शिक्षक को खो दिया। उनकी पुस्तकें, व्याख्यान और विचार आज भी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं। उनकी विरासत इस बात में निहित है कि उन्होंने ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब किसी व्यक्ति के विचार लोगों को बेहतर कार्य करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं, तब उसका प्रभाव जीवनकाल के बाद भी बना रहता है।

सपनों को कर्म में बदलने की प्रेरणा

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, परिश्रम और राष्ट्र सेवा की ऐसी प्रेरक गाथा है, जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। रामेश्वरम के साधारण परिवेश से निकलकर अंतरिक्ष अनुसंधान, मिसाइल विकास और राष्ट्रपति पद तक पहुंचे कलाम ने सिद्ध किया कि शिक्षा, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उनकी विरासत वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने विज्ञान को सामाजिक कल्याण से जोड़ने, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाने और युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया। आज तकनीकी नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास के माध्यम से विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में उनके विचार मार्गदर्शक हैं। कलाम का जीवन सिखाता है कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए ज्ञान, अनुशासन, ईमानदारी और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सपनों की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वे कर्म में बदलें और उनका लाभ समाज तक पहुंचे। उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों को अपनी क्षमताएं पहचानने, चुनौतियों से सीखने और ज्ञान तथा कर्म के माध्यम से राष्ट्र एवं मानवता की सेवा करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

Created by Universal Document Converter

जीडीसी मढ़हीन में नशे के खिलाफ स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित

संवाददाता

कठुआ, 16 अक्टूबर । राजकीय डिग्री कॉलेज मढ़हीन

में शुक्रवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से जुड़े मुद्दों विषय पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. डॉ. अनुपमा गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त समाज का संदेश देना था।

प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रभावशाली नारों के माध्यम से नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों को उजागर किया। प्राचार्य प्रो. डॉ. अनुपमा गुप्ता ने विद्यार्थियों की भागीदारी की सराहना करते हुए उन्हें नशामुक्त जीवनशैली अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन रोशन लाल, डॉ. शल्लू रानी और प्रो. मनु सैनी ने किया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. अरुण देव सिंह, प्रो. अनूप शर्मा और डॉ. मुनीषा देवी ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशामुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।

'देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, अब तो मैं कहूंगा नहीं, अब तो करके दिखाया जाएगा'– बाबा उमाकान्त जी महाराज

'नामध्वनि से लोगों को तकलीफों में बहुत आराम मिला इसीलिए इसको भूलो मतय खुद भी बोलो और परिवार वालों को भी बुलवाओ

संवाददाता

जम्मू। सीकर, राजस्थान परम् पूज्य परम् सन्त बाबा उमाकान्त जी महाराज ने सतसंग में कहा कि आप लोग जगह–जगह पर सन्तमत का प्रचार करो। जो जीव संस्कारी हैं, जब आप उनको समझाओगे तो वे सब आपकी बातों को सुनेंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। मैं अकेला कहां–कहां जाऊंगा, किसको–किसको समझाऊंगा? लेकिन आप संगत के जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप अगर मेरे हाथ–पैर बन जाओगे, मेरी बुद्धि, दिल–दिमाग बन जाओगे और गुरु का नाम लेकर आगे बढ़ जाओगे तो परिवर्तन हो जाएगा।

जैसे आज लोग कहते हैं कि बंदर और भालुओं ने परिवर्तन करके दिखा दिया, गोपी और ग्वालों ने परिवर्तन करके दिखा दिया। किया तो राम ने, किया तो कृष्ण ने लेकिन लोगों ने

कहा कि बंदर, भालुओं ने कमाल दिखा दिया, गोपी और ग्वालों ने मेहनत करके कमाल दिखा दिया, अत्याचार का अंत कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। ऐसे ही आप, जिनको लोग छोटा कहते हैं, गँवार कहते हैं, आप काम करके दिखा दोगे। इसीलिए हिम्मत करो, हौसला लाओ और आगे बढ़ो। जो जहां पर जैसा कर सकते हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे जवान हो चाहे बच्चे हो, आप लोग इस परिवर्तन की बेला में अपने–अपने स्तर से लगो। देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब तो मैं कहूंगा नहीं, अब तो करके दिखाया जाएगा।

एक सतसंगी ने बताया कि उनका जुकाम जो जा ही नहीं रहा था, जबसे नामध्वनि बोलने लगे, वह रफूचक्कर हो गया

'जय गुरु देव' नामध्वनि पहले खूब चली थी, उससे लोगों को तकलीफों में बहुत आराम मिल गया। एक सतसंगी ने बताया कि,

'हमको जुकाम नहीं छोड़ता था, कान बंद हो गया था, लेकिन जबसे हम नामध्वनि बोलने लगे हमारा जुकाम रफूचक्कर हो गया।'

लेकिन आप लोग नामध्वनि को भूल जाते हो। बस वही याद रहता है कि कैप्सूल ले लो और ठीक हो जाओ, लेकिन वही कैप्सूल अंदर विकार पैदा कर देता है, अंदर जगह बना लेता है और आपकी खुराक बन जाता है। इसीलिए आप नामध्वनि मत भूला करो, चलते–फिरते, उठते–बैठते बोलते ही रहा करो और घर में भी लोगों को बुलवाओ। नामध्वनि इस तरह बोली जाती है, 'जयगुरुदेव जयगुरुदेव जयगुरुदेव जय जयगुरुदेव'।

एबीएचआईएम के तहत ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश

संवाददाता

कठुआ, 16 अक्टूबर। जिला कठुआ में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उपायुक्त राजेश शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी की स्थापना की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय रैना ने उपायुक्त को मिशन के उद्देश्यों, प्रमुख घटकों और प्रस्तावित ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना संबंधी जानकारी दी। उपायुक्त ने प्रस्तावित प्रयोगशालाओं के लिए चिन्हित स्थलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को आपसी समन्वय से दूर किया जाए ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो। उपायुक्त ने एचएससीसी इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ बनी उपमंडल का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर कर अगले शुक्रवार तक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीसी ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना से रोगों की निगरानी, जांच सुविधाओं और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को परियोजना की नियमित निगरानी करने तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीपीओ कठुआ रंजीत ठाकुर, एएच जीएमसी कठुआ के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज नागपाल, विभिन्न ब्लॉकों के चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) और स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनन पर एसीबी का बड़ा एक्शन, माइनिंग अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज

संवाददाता

जम्मू, 16 अक्टूबर। जम्मू–कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन, निर्धारित सरकारी दरों से अधिक वसूली और ई–चालानों में कथित हेराफेरी के मामले में माइनिंग विभाग के अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस संबंध में एसीबी पुलिस थाना ऊधमपुर में एफआईआर नंबर 09/2026 दर्ज की गई है। मामले में सहायक माइनिंग इंजीनियर राजीव, जम्मू जिला माइनिंग अधिकारी रियासी रमेश्वर सांगरा, स्वर्ण सिंह राठौर सहित अन्य निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। एसीबी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में कुछ निजी खनन संचालकों और स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लघु खनिजों के कथित

निष्कर्षण तथा खनन पट्टों की वैधता समाप्त होने के बाद भी गतिविधियां जारी रखने के आरोप सामने आए हैं। जांच में यह भी आरोप सामने आए हैं कि कुछ संचालकों ने सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमतें वसूलीं और ई–चालानों का कथित दुरुपयोग करते हुए उनमें हेराफेरी की। इसके अलावा आवश्यक कंसेंट टू ऑपरेट की वैधता समाप्त होने के बावजूद कुछ स्टोन क्रशर इकाइयों के संचालन किए जाने के आरोप भी हैं।

एसीबी की जांच के अनुसार संबंधित सरकारी कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से निजी संचालकों को इन गतिविधियों में मदद मिलने की आशंका है। ब्यूरो अब प्रत्येक आरोपी की भूमिका, अवैध खनन और परिवहन की वास्तविक मात्रा, अधिक वसूली तथा इससे सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान का पता लगा रहा है। मामले की जांच के तहत एसीबी ने आरोपियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान भी शुरू किया है। ब्यूरो के मुताबिक छापेमारी और जांच की कार्रवाई जारी है। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, सरकारी पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आरोपों की पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: 1408, G H Skara, Near Ladakh Public School, Leh-Ladakh, Ladakh - 194101, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter